● वर्ष-5
● अंक-197
रायपुर, शनिवार
04 अप्रैल 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

छत्तीसगढ़ शासन | छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प



बस्तर की यह नई पहचान आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यह क्षेत्र अब शांति, प्रगति और गौरव की राह पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हम कृतज्ञ हैं.....

माँ दंतेश्वरी और जनजातीय नायक वीर गुण्डाधुर की यह धरती छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 को माओवादी आतंक से मुक्त हुई है। हिंसक माओवादी विचारधारा ने न जाने कितनी माँओं की कोख उजाड़ दी, बहनों का सुहाग और मासूमों के सिर से पिता का साया छीन लिया। देश के लिए लड़ते हुए हजारों जवान शहीद हुए। दशकों से सशस्त्र माओवाद देश के विकास को खोखला करता रहा, वर्ष 2014 में आपके आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और दृढ़ संकल्प तथा सुनियोजित रणनीति के माध्यम से माओवादी हिंसा पर कठोर प्रहार किया गया। अनेक राज्य सशस्त्र माओवाद से मुक्त हुए लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ महतारी और हमारे पड़ोसी राज्यों में यह नासूर बचा हुआ था। आपने पुनः आशीर्वाद दिया और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाई। पिछले ढाई सालों में आपकी सरकार ने सामूहिक संकल्प के बल पर इस सशस्त्र माओवादी नासूर को नष्ट कर दिया।

हम कृतज्ञ हैं उन शहीद जवानों के प्रति, जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति देकर देश को माओवाद से मुक्ति दिलाई। हम कृतज्ञ है हमारे सुरक्षा बल के जवानों के प्रति, जिन्होंने साहस और संकल्प के साथ अपनी जान पर खेलकर माओवाद की जड़ पर कड़ा प्रहार करके उसका समूल नाश किया।



हम कृतज्ञ हैं बस्तर की जनता का, जिन्होंने माओवादी हिंसा को न केवल अस्वीकार किया अपितु उसके विरोध में खड़े हुए। मुझे आपका जज्बा याद आता है जब सशस्त्र माओवादियों द्वारा वोट देने पर ऊंगली काट देने की धमकी दी जाती थी, तब भी आप निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करते थे। आपके मतदान से एक ऐसा नेतृत्व आया जिसने एक दशक के भीतर आंतरिक सुरक्षा के इस सबसे बड़े संकट को समाप्त कर दिया।

हम कृतज्ञ हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसपूर्ण नेतृत्व के प्रति। मुझे याद है वर्ष 2015 में दंतेवाड़ा में उन्होंने अपनी सभा में हथियार उठाने वाले युवाओं से कहा था 'एक प्रयोग कीजिए, पांच दिन हथियार रख दीजिए, उस परिवार के बच्चे के साथ दिन गुजारिए जिसने आपकी वजह से अपने परिजनों को खोया है फिर आप कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जाएंगे।'

प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया, मार्गदर्शन किया है। उनके दृढ़ संकल्प की बदौलत देश माओवादी हिंसा से मुक्त हुआ है। हिमालय जैसी चुनौतियों से निपटने के उनके साहस ने हमें उत्साह से भर दिया और हमने यह असंभव जैसा लक्ष्य प्राप्त किया।

हम कृतज्ञ हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के , जो माओवादी नासूर को नष्ट करने के लिए बनायी गई रणनीति के शिल्पी हैं । रायपुर में पत्रकारों की भरी सभा में आपने देश से वायदा किया था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करेंगे और इसे पूरा किया। आपने माओवादी आतंक को नष्ट करने के लक्ष्य पर नजर टिकाए रखी। हमारा नेतृत्व किया, संसाधन और मार्गदर्शन दिया। हमारे बहादुर जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। आपने गोली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बोली से देने का संदेश दिया। माओवादी हिंसा को छोड़कर जो शांति की राह पर लौटे, संविधान को अपनाया, उनका हमने स्वागत किया।

हम कृतज्ञ हैं प्रदेश की जनता के प्रति जो इस सुंदर धरती को सशस्त्र माओवाद से मुक्त कराने के रास्ते में सहभागी बनी, आपने हम पर विश्वास किया। विश्वास कीमती होता है, हमने इसकी रक्षा की है। बस्तर में बच्चे अब निर्भय होकर स्कूल जाएंगे, माताएं-बहनें आजादी की सांस लेंगी और हर तरफ विकास का उजाला फैलेगा।

अब कहीं रेड कॉरिडोर नहीं, हर तरफ ग्रीन कॉरिडोर है।
एक सुखद उज्ज्वल भविष्य की राह पर हम सब सहभागी बन अब आगे बढ़ेंगे।

जय भारत, जय छत्तीसगढ़



आपका **विष्णु देव साय** मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

सांख्य-47391/153

संक्षिप्त समाचार

बंगाल चुनाव में अमित शाह के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालेंगे विजय शर्मा



रायपुर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने जनता को अपने पक्ष में रिझाने की पूरी ताकत लगा रही है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष में बैठी टीएमसी फिर से सरकार बनाने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है तो दूसरी ओर भाजपा भी यहां पर सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को भाजपा ने बंगाल चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की 150 सीटों पर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संगठन में बड़ी ताक़त है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता प्रशिक्षित और समर्पित हैं इसलिए छत्तीसगढ़ की टीम को कई राज्यों में भेजा गया। बंगाल में भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा परिणाम आएगा।

फुटबॉल में छत्तीसगढ़ को रजत पदक फाइनल में पश्चिम बंगाल से मिली हार



रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत शुक्रवार को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम, कोटा में खेले गए पुरुष फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में छत्तीसगढ़ को पराजय का सामना कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल मैच में दोनों टीमों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को रोमांचित किया। छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार तालमेल, तेज आक्रमण और मजबूत रक्षा का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए हर पल मुकाबले को संतुलित बनाए रखा। हॉफ टाइम तक पश्चिम बंगाल की टीम 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी। छत्तीसगढ़ की टीम ने लगातार आक्रमण कर गोल उतारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, विभिन्न विभागों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी और खेलप्रेमी बड़ी संख्या में फाइनल मैच देखने के लिए मैदान में पहुंचे थे।

बोर्ड परीक्षा के परिणाम सुधारने कॉल आए तो तुरंत करें पुलिस में शिकायत : माशिमं



रायपुर। छत्तीसगड माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के उपरांत वर्तमान में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। पूर्व वर्ष 2024 एवं 2025 में बोर्ड परीक्षा में पास करने के लिये छात्रों/पालकों को फर्जी फोन कॉल आये थे। फर्जी कॉलर व्दारा परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु अनुचित मांग की गई थी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल व्दारा संज्ञान में लेते हुए बोर्ड परीक्षा में पास करने के लिये छात्र/छात्राओं एवं पालकों को किसी भी प्रकार का फर्जी फोन कॉल आते हैं तो उसे ध्यान न देते हुये अनावश्यक किसी प्रकार का लेन-देन की कार्यवाही न करें तथा उक्त फर्जी कॉल के संबंध में अपने नजदीकी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करें। इस प्रकार के फर्जी कॉल का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से कोई संबंध नहीं है। अतः छात्र/अभिभावक फर्जी कॉल से भ्रमित न होवें एवं सतर्क रहे।

ग्रीष्मकालीन शिविर का हुआ समापन एवं सुधर्म भवन का शिलान्यास

रायपुर। श्री सुधर्म स्थानकवासी जैन श्री संघ रायपुर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन धार्मिक शिक्षण शिविर 2026 का समापन एवं सुधर्म भवन का शिलान्यास कार्यक्रम विगत दिनो भवन शिलान्यास सुधर्म जैन विहार, भैरव सोसाइटी रायपुर में संपन्न हुआ.उक्त जानकारी देते हुए अजय जैन ने बताया कि विगत 41 वर्षो से श्री सुधर्म परिवार रायपुर द्वारा ग्रीष्मकालीन धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेमचंदश्रीश्रीमाल एवं विशेष अतिथि श्री मोतीलाल कांकरिया एवं श्री पारसमल बोथरा थे .उक्त अवसर पर श्री सुधर्म स्थानकवासी जैन श्री संघ रायपुर अध्यक्ष प्रेमचंद गोलछा महामन्त्री कमल बोहरा विशेष रूप से उपस्थित थे.शिविर में अध्यापन खीचन गुरुकुल के ओजस्वी सुश्रावक श्री विद्यासागर एवं सहयोगी टीम जोधपुर द्वारा करवाया गया. शिविर में लगभग 800 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया.शिविर के लाभार्थी परिवार पूज्य माताश्री स्व. रंभा देवी एवं पूज्य पिताजी स्व. पुखराज जी गोलछा की स्मृति में श्री मूलचंद श्री श्रीचंद गोलछा परिवार थे।

बस्तर से सुरक्षाबल की वापसी को लेकर भूपेश के सवाल पर साव का पलटवार

कहा- अपनी सरकार में पुलिस और जवानों के हाथ बांध दिए थे



रायपुर। भूपेश बघेल कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो। इन्हें प्रदेश के विकास और खुशहाली से कोई लेना-देना नहीं है। जब समय आएगा तो सुरक्षा जवान भी लौटाए जाएंगे। यह बात उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बार-बार नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर से सुरक्षाबल के लौटने को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर कही।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में भूपेश बघेल के सवाल को लेकर कहा कि अपनी सरकार में पुलिस और जवानों के हाथ बांध दिए थे। जब इनकी सरकार बनी तो नक्सलियों ने खुशी मनाई थी। आज भी इनकी मंशा बार-बार स्पष्ट हो रही है।

वहीं 16,000 नक्सल प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमने हर तैयारी से अभियान शुरू किया था। जब नक्सली सरेंडर करेंगे तो उनकों अच्छा पुनर्वास मिले। दूसरी ओर आम लोगों को सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जाए। इस तैयारी का बड़ा प्रतिफल हमें मिला है। इतने कम समय में नक्सलवाद समाप्त हुआ है।

पश्चिम बंगाल में स्ट्रक्र की प्रक्रिया से जुड़े न्यायिक अधिकारी को बंधक बनाए जाने और उस पर आई सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर अरुण साव ने कहा कि हम बार-बार कहते रहे कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है। पश्चिम बंगाल संविधान से नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। आज पश्चिम बंगाल की जनता उनसे परेशान है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी।

वैट में छूट खत्म होने से पेट्रोल के दाम बढ़ने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता मजबूती से सरकार के साथ खड़ी है। हम मिलजुल कर ही इस चुनौती का सामना करेंगे। वैश्विक स्थिति ठीक होने से स्थिति में सुधार होगा। वहीं पूर्व विधायक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े मनीष कुंजाम के बड़ी डील होने पर नक्सली कमांडर ने समर्पण करने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कुंजाम का आरोप बेबुनियाद और निराधार है। नक्सलियों में स्वेच्छा से सरेंडर किया है। हमारी सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर सरेंडर किया है।

'अब जेलों में बंद नक्सलियों का होगा पुनर्वास'

- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताई नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने की सरकार की नई रणनीति



जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की धरती से हमेशा के लिए नक्सलवाद का दंश खत्म हो जाए इसके लिए सक्रिय नक्सलियों के पुनर्वास की योजना लेकर आई, जिसका असर देखने को मिला। अब साय सरकार जेल में कैद नक्सलियों के भी पुनर्वास करने की योजना तैयार करने में जुटी है।

बीते 2 वर्षों में 500 से अधिक माओवादी मारे गए, 3 हजार माओवादियों ने पुनर्वास किया। करीब 2 हजार माओवादियों की गिरफ्तारियां भी हुई है। नक्सल मामलों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जेलों में बंद माओवादी जो छुट-पुट घटनाओं में शामिल रहे। ऐसे माओवादियों के प्रकरण को वापस लेने और उनका पुनर्वास कराने की योजना सरकार की है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा था कि सरकार की पुनर्वास नीति केवल कागज का पुलिंदा नहीं है, और केवल ईनाम की राशि नहीं है। पुनर्वास नीति में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम भी शामिल है। पुनर्वास नीति के माध्यम से यह कल्पना सरकार की है कि यदि जंगल से पुनर्वास हो सकता है, तो जेलों से भी पुनर्वास किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जंगल से पुनर्वास किए माओवादी जेलों में जाकर अपने परिजनों और अपने मित्रों से मिलते हैं। अगले चरण में जेलों में बंद माओवादियों को पैरोल पर निकालकर पुनर्वास केंद्रों में लाकर मिलाया जाएगा। और जिन्होंने पुनर्वास किया है वे जेलों में बंद माओवादियों को पुनर्वास के लिए प्रेरित करेंगे। जिसके बाद सरकार उनके जमानत के लिए कार्य करेगी। और जमानत पर आकर पुनर्वास केंद्रों में रहकर सामान्य जीवन जी सकते हैं।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने महतारी वंदन योजना मददगार

रायपुर। महिलाओं के साथ असमानता को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाने, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगी, जिसे मलिाओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने उपयोग करने लगी।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के छोटे से ग्राम मझगंवा की श्रीमती हेमा सिंग की कहानी आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली हेमा सिंग ने आज अपने आत्मविश्वास और सरकारी योजना के सहयोग से अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है। महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगी। जिसे हेमा सिंग ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। हेमा सिंग ने इस राशि को बचाकर अपने घर के पास एक छोटा सा किराना स्टोर शुरू किया। धीरे-धीरे उनकी दुकान चल निकली। गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए उनका व्यवसाय बढ़ने लगा और आय में भी स्थिरता आने लगी। आज उनकी दुकान न सिर्फ उनकी आर्थिक मजबूती का आधार बनी है, बल्कि उनके परिवार के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव लाई है। हेमा सिंग अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रही हैं और भविष्य के लिए भी बचत कर रही हैं। पहले जहां रोजमर्रा के खर्चों को लेकर चिंता बनी रहती थी, वहीं अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष साफ नजर आता है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को लगातार आर्थिक मजबूती मिल रही है।

जल संरक्षण के कार्यों को और गति दें, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर संरक्षित करें : डेका

राज्यपाल ने सरायपाली में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली



रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जल संरक्षण के कार्यों की सराहना करते हुए किसानों को डबरी खनन के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि विकासखंड में 218 डबरी स्वीकृत की गई हैं तथा बड़ी संख्या में निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं, राज्यपाल ने और गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल श्री डेका ने आज सरायपाली प्रवास के दौरान रेस्ट हाउस में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

राज्यपाल ने वृक्षारोपण को जनआंदोलन के रूप में संचालित करने पर जोर देते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जाए। कैंपा एवं मनरेगा मद से वृहत वृक्षारोपण करते हुए शासकीय भवनों, रेस्ट हाउस परिसरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार एवं छायादार पौधे लगाए जाएं। विभाग ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख पौधरोपण किया गया है तथा अमृत सरोवरों के आसपास भी हरित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने इसमें जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने तथा धान के साथ उद्यानिकी फसलों के समावेश पर बल दिया। उन्होंने जैविक चावल के वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रभावी बनाने, हितग्राहियों से सेवा शुल्क लेने तथा सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने टीबी रोगियों की जानकारी ली और उनके उपचार की सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने समाज के सक्षम व्यक्तियों को टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने, रेडक्रॉस से जुड़ने तथा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एवं मोतियाबिंद के उपचार हेतु जागरूकता अभियान एवं शिविर आयोजित करने पर बल दिया। उन्होंने एम्स से समन्वय स्थापित कर बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

राज्यपाल श्री डेका ने योग को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों में प्रारंभ से ही योग की आदत विकसित की जाए तथा इसके लिए नियमित प्रशिक्षण और कक्षाएं संचालित की जाएं। उन्होंने अधिक से अधिक पुस्तकालय खोलने तथा महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर लखपति दीदी बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए।

निस्तारी पानी की समस्या से निजात दिलाने गंगरेल का पट 500 क्यूसेक डिस्चार्ज के साथ खोला गया



रायपुर। दिनोदिन बढ़ते गर्मी के साथ ग्रामों में व्याप्त हो रहे निस्तारी पानी की समस्या व भूगर्भीय जल स्त्रोत के नीचे जाते जाने से पेयजल संकट गहराने की ओर शासन - प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराये जाने के बाद हरकत में आये प्रशासन ने बीते बुधवार को समस्या से निजात दिलाने गंगरेल का पट खोल दिया है लेकिन यह पानी समाचार लिखे जाने तक लखौली नहीं पहुंचा है। जानकारी के अनुसार शुरुआती 5 सौ क्यूसेक के डिस्चार्ज को दो भागों में बांट महानदी मुख्य नहर व मांढर शाखा नहर में प्रवाहित किया जा रहा है जिसके चलते पानी की दौड़ काफी धीमी है। सूत्रों के अनुसार डिस्चार्ज को क्रमशः धीरे - धीरे बढ़ाया जावेगा और इसकी शुरुआत कर दी गयी है।

ज्ञातव्य हो कि गर्मी के चलते तालाबों के सूखते जाने की वजह से ग्रामों में जहां निस्तारी संकट उठ खड़ा होना शुरू हो गया है वहीं भूगर्भीय जल स्त्रोत के नीचे जाते जाने की वजह से पेयजल समस्या भी सामने आना शुरू हो चुका है जिसे की तालाबों के भरने से एक सीमा तक रोका जा सकता है। ग्रामीणों की मांग व ज्वलंत समस्या को देखते हुते बीते मंगलवार को जहां बंगोली सिंचाई उपसंभाग के अधीन आने वाले 10 सिंचाई पंचायतों के पूर्व अध्यक्षों ने जहां विभागीय अधिकारियों से अविलंब गंगरेल से निस्तारी पानी छोडने की गुहार लगाई थी वहीं रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय व मुख्य सचिव विकासशील सहित क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल को मेल से ज्ञापन भेज गंगरेल से निस्तारी पानी छुड़वाने का आग्रह किया था। इसके पहले अभनपुर क्षेत्र से विधायक रहे पूर्व सिंचाई मंत्री धनेन्द्र साहू ने भी निस्तारी पानी की समस्या को लेकर शासन - प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था।

सिंचाई पंचायतों के अध्यक्ष रहे हिरेश चंद्राकर , तुलाराम चन्द्राकार, गोविंद चंद्राकर, चिंताराम वर्मा, प्रहलाद चंद्राकर, मनमोहन गुप्ता, भारतेन्दु साहू, धनीराम साहू,थानसिह साहू ने डिस्चार्ज बढ़ाने की मांग के साथ - साथ पानी के व्यर्थ बरबादी को रोकने पर्याप्त मैदानी अमला की व्यवस्था करने व संबंधित यंत्रियों तथा सिंचाई अनुविभागीय अधिकारियों को सतत् दौरा सुनिश्चित कराने का आग्रह विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से किया है।

आदर्श मंडल के रुप में पहचान बनाई रायपुर रेल मंडल ने

रायपुर। रायपुर मंडल ने राजस्व, संरक्षा, तकनीकी नवाचार एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 अनेक उपलब्धियां करते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आर्दश रेल मंडल के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। यह जानकारी मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में मीडिया कर्मियों के साथ साझा की।

रायपुर रेल मंडल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए श्री दयानंद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में रायपुर मंडल ने राजस्व, संरक्षा, तकनीकी नवाचार एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय रेल में एक आदर्श मंडल के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। माल लदान में रायपुर रेल मंडल ने लक्ष्य से अधिक 4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। वाणिज्य प्रबंधक श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 -26 में 03.87 प्रतिशत (लगभग 04 प्रतिशत) की वृद्धि हासिल की है और 46.44 मिलियन टन लदान कर 4983 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया हैं । वित्तीय वर्ष 2025-26 में रायपुर मंडल को 46.33 मिलियन टन लदान का लक्ष्य दिया गया था। रायपुर मंडल ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024 -25 में 44.73 मिलियन टन लदान कर 4818 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया था। इस उपलब्धि के पीछे आधुनिक लोडिंग अवसंरचना, ग्राहक-केंद्रित नीतियाँ, डिजिटल पहल तथा विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अब्दुल फताह की छलांग ने लक्षद्वीप एथलेटिक्स के लिए एक नया अध्याय लिखा

- वह लक्षद्वीप के पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं, जिन्होंने लंबी कूद में 7 मीटर की दूरी तय की

रायपुर। अब्दुल फताह ज़्यादातर रातों को समुद्र में होते हैं, जहां वे मछुआरे बनकर अपने परिवार की रोज़ी-रोटी कमाने में मदद करते हैं। जैसे ही सुबह होती है, वे सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर निकल पड़ते हैं और एक एक अलग सपने का पीछा करते हुए लक्षद्वीप को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पहला मेडल दिलाया। कवरत्ती और कदमत द्वीपों के बीच स्थित, दूरदराज के अमीनी द्वीप जो लगभग 2.7 किमी लंबा और 1.2 किमी चौड़ा है, और जिसका कुल भू-क्षेत्रफल 2.60 वर्ग किमी है के 18 वर्षीय लॉन्ग जम्पर ने जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर मैदान में 7.03 मीटर की अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। यह इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। केंद्र शासित प्रदेश के खेल अधिकारी अहमद जावेद हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह लक्षद्वीप के पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 7 मीटर की दूरी पार की है और यह वाकई एक खास बात है।

मछुआरे परिवार में जन्मे फताह भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं और घर की बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद, आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। इसके बजाय, उन्होंने अपने पिता के पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बँटाने और खेल को अपने जुनून के तौर पर अपनाने का फ़ैसला किया।फताह ने कहा, कोई और चारा नहीं है, आपको चीज़ों में संतुलन बनाना ही पड़ता है। जब मैं स्कूल में था, तभी से मैं अपने पिता की मछली पकडने के काम में मदद करता आ रहा हूँ। यही हमारी आमदनी का एकमात्र ज़रिया है। हमारे परिवार में छह लोग हैं। सुबह मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ; मेरे परिवार को इस बारे में पता है, भले ही वे इस खेल के बारे में बहुत कम समझते हों।

दिलचस्प बात यह है कि एथलेटिक्स उनका पहला प्यार नहीं था। फताह शुरू में फुटबॉल खेलते थे, जैसा कि द्वीप के कई दूसरे युवा करते थे। हालांकि, कुछ साल पहले एक स्थानीय इंटर-आइलैंड प्रतियोगिता के दौरान उनकी यात्रा में एक



अहम मोड़ आया। कोच मोहम्मद कासिम ने इस युवा की दौडने की ज़बरदस्त काबिलियत को पहचाना और उन्हें एथलेटिक्स में आने का सुझाव दिया। तब से, फताह ने लॉन्ग जंप और 100-मीटर स्प्रिंट में ट्रेनिंग शुरू कर दी। लगभग उसी समय, अमिनी एथलेटिक्स एसोसिएशन का गठन होने लगा, जिससे इस क्षेत्र में खेलों के विकास को एक सही ढाँचा मिला।

फताह और कई अन्य युवा एथलीटों को धीरे-धीरे कोचिंग की मदद दी गई, जिससे उन्हें ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग करने में मदद मिली। सिर्फ़ दो सालों में, एसोसिएशन ने लगभग 384 एथलीटों को तैयार किया। इस समूह में से, 17 एथलीटों को गेम्स में लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। जगदलपुर में फत्ताह की 7.03 मीटर की गोल्ड-विनिंग जंप, वहां के हालात को देखते हुए, खास तौर पर संतोषजनक थी। ट्रेनिंग के दौरान, उन्होंने बताया था कि उनकी जंप आमतौर पर 6.5 से 6.7 मीटर के आस-पास रहती है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में आने से पहले, मैंने अपने लिए 7.15 मीटर तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया था। मुझे खुशी है कि मैं सात मीटर का आँकड़ा पार कर पाया, और यह गोल्ड मेडल मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।

लक्षद्वीप धीरे-धीरे भारत के एथलेटिक्स के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे जानी-मानी एथलीटों में से एक हैं मुबस्सिना मोहम्मद, जो 19 साल की लॉन्ग जंपर और हेप्टाथलीट हैं। कुवैत में हुए 2022 एशियन 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतकर वह लक्षद्वीप की पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनीं। उन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में 6.30 मीटर के अपने पर्सनल बेस्ट के साथ जूनियर नेशनल टाइटल भी जीता।

मुबस्सिना की तरह, फताह भी बिना किसी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा के ट्रेनिंग करते हैं। लक्षद्वीप, जो सिर्फ़ 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है और जिसकी आबादी 70,000 से भी कम है, वहां अभी तक कोई ठीक-ठाक सिंथेटिक ट्रैक या एथलेटिक्स स्टेडियम नहीं है। नतीजतन, कई एथलीट मिट्टी के ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हैं, जबकि फत्ताह अक्सर अपने स्प्रिंट इवेंट्स की ट्रेनिंग के लिए पास के एक फुटबॉल मैदान का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स और दूसरे नेशनल लेवल के मुकाबलों में हमारी सफलता को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि हमारे लिए हालात बदलेंगे। हो सकता है कि हमें कुछ नौकरियाँ और ट्रेनिंग की सुविधाएँ मिल जाएं।

● वर्ष-5

● अंक-197

रायपुर, शनिवार
04 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8› मल्लखंभ में लहराया परचम...

जनजातीय समाज और खेल का रिश्ता सदियों पुराना : सीएम साय

समापन समारोह में बॉक्सर मेरीकॉम और फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया हुए

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल आडिटोरियम रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो जोश और ऊर्जा देखने को मिली, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश की आदिवासी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने और उनकी खेल क्षमता को सामने लाने का अनूठा अवसर साबित हुआ है।

मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके विजन और मार्गदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ। साथ ही केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के निरंतर सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उनके



प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज देश के खेल मानचित्र में प्रमुख स्थान पर स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब यह गेम्स प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज और खेल का रिश्ता सदियों पुराना है। तीरंदाजी, दौड़ और कुश्ती जैसे खेल जनजातीय जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उन्होंने स्वयं के जनजातीय पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समाज में अपार ऊर्जा और प्रतिभा निहित है, जिसे सही मंच मिलने पर देश-विदेश में पहचान मिल सकती है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश की एकता, संस्कृति और कौशल का महाकुंभ बनकर उभरा है। देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय खिलाड़ियों ने इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह आयोजन आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने और खेलों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खिलाड़ियों ने केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि साहस और उत्कृष्टता की नई कहानियां रचने के लिए प्रतिस्पर्धा की है। उन्होंने यह साबित किया है कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि बस्तर, सरगुजा, झारखंड और पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में भी भरपूर है।

समारोह में मुख्यमंत्री साय ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कर्नाटक, द्वितीय स्थान ओडिशा और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने कुल 19 पदक (03 स्वर्ण, 10 रजत और 06 कांस्य) हासिल किए हैं।

जन विश्वास विधेयक-2 लागू

विश्वास-आधारित शासन का एक नया युगः गोयल

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास विधेयक -दो को विश्वास-आधारित शासन का एक नया युग! बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इस विधेयक में देश भर की अदालतों में लंबित अनुमानित 5 करोड़ मुकदमों का बोझ कम होने की संभावना है।श्री गोयल ने जन विश्वास (उपबंध संशोधन) विधेयक 2026 को गुरुवार को पारित होने के साथ संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद शुक्रवार को यहां इस विधेयक को लेकर एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा इस विधेयक के जरिए कुल 79 केंद्रीय कानूनों में 1000 उपबंधों को संशोधित, समाप्त या उनमें आपराधिक कार्रवाई के प्रावधानों को समाप्त किया जा रहा है। इनमें से छह कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। श्री गोयल के साथ उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया भी थे। वाणिज्य मंत्री ने कहा इसके



माध्यम से कई जगह भूल चूक या छोटी मोटी गलती पर भी जुर्माने के प्रावधानों को हटा कर अर्थदंड लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे इस समय पूरे देश में अदालतों में चल रहे अनुमानित पांच करोड़ मुकदमों का त्वरित निस्तारण होने की संभावना बनी है। उन्होंने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में भी संसद की तरह यह स्पष्ट किया कि इन कानूनों के उपबंधों में संशोधन पिछली तारीख से करना कठिन था। पर इसके आधार पर स्थानीय प्रशासन अब पहले से चल रहे मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया को नये संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। श्री गोयल ने कहा कि जन विश्वास विधेयक-1 में कुल विभिन्न कानूनों के कुल 183 उपबंधों में संशोधन का असर बहुत सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों ने अपने कानूनों को लेकर जन विश्वास विधेयक लाने की प्रकिया में हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा, जन विश्वास विधेयक 2026 वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के जीवन जीने की आसानी और कारोबार की आसानी को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से अनुपालन का कम बोझ नागरिकों, एमएसएमई, छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को लाभ पहुंचाएगा, जिससे एक अधिक सक्षम और पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण होगा। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक जन विश्वास विधेयक, 2026 विश्वास-आधारित शासन व्यवस्था की दिशा में एक निर्णायक कदम है।



पुदुच्चेरी । पुदुचेरी में चुनावी माहौल को गरमाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला अजंता सिग्नल से शुरू होकर कामराजर प्रतिमा तक चला। लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को तय करने में करीब एक घंटे का समय लगा। इस दौरान पीएम के साथ मुख्यमंत्री और एआईएनआरसी नेता एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमसिवायम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जनता ने उन पर फूलों की बारिश की।रोड शो के दौरान पूरे शहर में भाजपा और एआईएनआरसी के झंडे नजर आ रहे थे। सडकों के दोनों ओर खड़े समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह-जगह पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कांग्रेस का दौर मतलब हिंसा और आंदोलनः नितिन नवीन

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को मतदाताओं से असम विधानसभा चुनाव में वोट डालते समय कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को ध्यान में रखने का आग्रह किया। भाजपा उम्मीदवार दिगंता कलिता के समर्थन में कमालपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नबीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने घुसपैठियों के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ की अनुमति दी और उसके कार्यकाल में महिलाएं और जमीनें असुरक्षित थीं। हालांकि, पिछले दस साल असम के विकास का दौर रहे हैं और मतदाताओं को मतदान करते समय पहले के दौर को याद रखना चाहिए।

नितिन नवीन ने आगे विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगा। नवीन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। उनके शासनकाल में महिलाएं और जमीन सुरक्षित नहीं थीं। उन्होंने दावा किया कि असम के लोगों की चुनी हुई भाजपा सरकार ने घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया और सिलसिलेवार तरीके से विकास कार्य शुरू किए। उन्होंने कहा कि असम में पिछले 10 साल विकास के रहे हैं। जब आप वोट देने जाएं, तो उससे पहले के दौर को जरूर



याद रखें। भाजपा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि सरमा के नेतृत्व में भाजपा फिर से सत्ता में लौटेगी और हैट्रिक लगाएगी। नवीन ने कहा कि वह 2009-2010 से पार्टी के विभिन्न कार्यों के लिए असम आते रहे हैं और राज्य के कई हिस्सों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उस समय विकास की कोई बात नहीं होती थी। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता था, तो तनाव रहता था।

प्रमुख समाचार

ईरान ने मार गिराया अमेरिकी लड़ाकू विमान

तेहरान। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। खबर है कि ईरान की सीमा के भीतर अमेरिका के एक लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद अमेरिकी सेना ने अपने लापता पायलटों और चालक दल को बचाने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच खबर आई है कि अमेरिकी सेना ने एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया है। वहीं, दूसरे पायलट और चालक दल के सदस्यों को ढूढ़ने की कोशिश जारी है। इससे पहले, सोशल मीडिया पर सामने आए फुटेज में अमेरिकी ड्रोन, विमान और हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी इलाके के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए, जहां पायलट लड़ाकू विमान से कूद गया था। हालांकि, ईरान के खातम अल-अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान में केशम द्वीप के दक्षिण में एक दूसरे पांचवीं पीढ़ी के अमेरिकी एफ-35 विमान को आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स की नई वायु रक्षा प्रणाली ने निशाना बनाकर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि पायलट के सुरक्षित विमान से बाहर निकलने की संभावना न के बराबर है।



राहुल ने मानहानि मामले में जारी समन को हाईकोर्ट में दी चुनौती

जबलपुर। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राहुल गांधी की तरफ से दायर पुनरीक्षण याचिका में मामले को रद्द किए जाने की राहत चाही गई है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह पर सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है। गौरतलब है कि साल 2018 के झाबुआ में हुई चुनावी सभा से राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम लिया था। राहुल गांधी ने तुलना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। इस बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था।



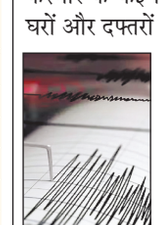
विशेष सत्र बुलाने पर मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं : पासवान

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम में संशोधन के संबंध में विशेष संसदीय सत्र बुलाने के एनडीए सरकार के फैसले की सराहना कर कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), ने हमेशा इसतरह के मुद्दे को बहुत महत्व दिया है। केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि महिलाएं इसकी मांग करती रही हैं और हमारी पार्टी ने लगातार इस मांग का समर्थन किया है, हमारे दिवंगत नेता राम विलास पासवान जी के समय से ही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि विपक्ष भी इस बिल का समर्थन करेगा।सरकारी सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में संसद का बजट सत्र पुनः बुलाने की तैयारी में है, ताकि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव करने वाला संशोधन विधेयक पेश किया जा सके। जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित रहेगी। एजेंडा में 2023 के नारी शक्ति वंदना अधिनियम में संशोधन और परिसीमन आयोग विधेयक को पेश करना भी शामिल हो सकता है।



खामोश करवाया गया हूं हारा नहीं हूं :राघव चड्ढा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर अपने सांसद राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटाने का आग्रह किया है। इसके बाद राघव चड्ढा ने इशारों-इशारों में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। राघव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आम आदमी को मैसेज देते हुए लिखा, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। आप ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी कहा है कि अब राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर बोलने का मौका न दिया जाए। इससे उनके बोलने के समय में भी कटौती की जा सकती है। बता दें राघव चड्ढा हाल के दिनों में संसद में कई जनहित के मुद्दों को जोर-शोर से उठा रहे थे। इनमें एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय का मुद्दा और डिलीवरी बॉयज से जुड़े सवाल शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने पैटरनिटी लीव (पितृत्व अवकाश) का मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने कहा कि बच्चे की परवरिश केवल मां की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि माता-पिता की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि राघव चड्ढा राज्यसभा में किन विषयों पर बोलने वाले हैं।



दिल्ली-एनसीआर 5.9 की तीव्रता से कांप उठी उत्तर भारत की धरती

नईदिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार रात 9ः42 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इससे लोगों में दहशत फैल गई. दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए. जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भी जमीन हिलने से लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. जानकारी के मुताबिक, भूकंप अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई. तेज झटकों के चलते ही दिल्ली, पंजाब और जम्मू-कश्मीर समेत कई इलाकों में धरती हिली.जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, पुंछ और कश्मीर घाटी के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. झटके कुछ सेकंड तक रहे, लेकिन उनकी तीव्रता इतनी थी कि लोग घबरा गए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागे. दिल्ली-एनसीआर में कई ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों ने झटकों को साफ महसूस किया. दफ्तरों और घरों में बैठे लोग तुरंत बाहर निकल आए. कुछ जगहों पर लोग पार्क और खुले मैदानों में इकट्ठा हो गए. फिलहाल, किसी बड़े नुकसान या जानमाल के हताहत होने की खबर नहीं है।

ईरान ने सारी दुनिया को बताई अपनी ताकत

सनत जैन

ईरान ने यूएई में स्थापित अमेजॉन का सर्विस डाटा सेंटर चेतावनी देने के दूसरे दिन ही उड़ा दिया। ईरान ने यह हमला ड्रोन से किया था, जो बिल्कुल सटीक था। इसमें कंपनी को काफी नुकसान हुआ। सरवर नष्ट हो जाने के कारण कंपनी की सारी सेवाएं प्रभावित हो गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में घोषणा कर चुके हैं कि वह युद्ध को खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको लेकर ईरान ने काफी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। जहां-जहां पर अमेरिकी सेवाएं संचालित हो रही हैं वहां-वहां पर ईरान ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरान की इस कार्यवाही से सारी दुनिया के देश हैरान हैं। ईरान का शाहिद नामक ड्रोन इस समय चर्चाओं में है। इस ड्रोन को लेकर सारी दुनिया के देशों में जिज्ञासा बनी हुई है। इसने वेब सेंटर में घुसकर जिस तरह से सटीक निशाने पर हमला किया वह आश्चर्यजनक था। ईरान अब खुलकर चेतावनी देकर जिस तरह से हमले कर रहा है उसके सामने अमेरिका और इजरायल का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। सारी दुनिया के देशों में तेल संकट के साथ-साथ अब खाद्य संकट की भी चर्चा हो रही है। करीब 96 देश अभी तेल संकट से जूझ रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं उसमें 125 से अधिक देशों में हार्मोज से जहाजों की आवाजाही में रुकावट से जो संकट पैदा हुआ है उससे अब तेल के साथ-साथ खाद्य संकट भी देखने को मिल रहा है। रही सही कसर जिस तरह से ईरान अमेरिकी कंपनियों पर हमला कर रहा है उससे खाड़ी देशों के साथ-साथ अन्य देशों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस तरह के समाचार आ रहे हैं उसमें 100 से अधिक देश अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण बुरी तरह से परेशान हैं। अमेरिका और इजरायल ने अपनी सभी शक्तियों का प्रदर्शन करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। बी-2 बंबर से सेकड़ों स्थानों पर हमला करके ईरान



को भारी नुकसान पहुंचाया। अब ईरान खुलकर इसका बदला ले रहा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल जिस तरह से सटीक निशाना लगाकर खाडी के देशों में अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों के साथ-साथ अब उनके महत्वपूर्ण कारोबार को नष्ट कर रहे हैं इसके कारण सारी दुनिया के देशों में एक नई दहशत फैल गई है। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के संचार माध्यमों को नष्ट किया है तथा जिस तरह से ईरान हमले करके तकनीकी आधार पर अमेरिका और इजरायल को धता बता रहा है उससे सारी दुनिया के देश हैरान हैं। ईरान की तकनीकी जिस तरह से इजरायल और अमेरिका का मुकाबला करते हुए जो ईरानी नवीन प्रयोग हो रहे हैं उससे सबसे ज्यादा परेशानी टेक कंपनियों को हो रही है। उनके सुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करते हुए ईरान द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसके कारण ईरान का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है जिस तरह से ईरान ने अब सरवर और इंटरनेट के जरिए सेवाओं पर निशाना साधना शुरू कर दिया है उसके कारण सभी देशों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान में बैंकिंग एवं अन्य सेवाएं इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा डाटा सर्वर से जुड़ा हुआ है। यदि उसमें कोई खराबी आती है तो करोड़ों लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ईरान ने पिछले एक माह में जिस तरह से इस युद्ध को लड़ा है उसने सारी दुनिया के देश हैरानी में हैं। ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइलें अत्याधुनिक संचार माध्यमों से लैस स्थलों को जिस तरह से वह अपने निशाने पर लेकर नुकसान पहुंचा रहे हैं उसने पूरी दुनिया के युद्ध समीकरण को बदल दिया है। तकनीकी क्षेत्र में इजराइल और अमेरिका को चुनौती, ईरान द्वारा दी जा रही है। इसकी कल्पना भी इस युद्ध के पहले किसी देश ने नहीं की थी। पिछले एक माह में ईरान ने जिस तरह से वैश्विक राजनीति और सोच को परिवर्तित किया है उसके बाद ऐसा लगता है सारी दुनिया में अब नए समीकरण बनना शुरू हो गए हैं। इसमें अमेरिका अलग-अलग पड़ता चला जा रहा है। हार्मोज को खुलवाने के लिए भारत, फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि लगभग 45 देश जिस तरह से ईरान के साथ बात कर रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट है भविष्य में अमेरिका का जो एकाधिकार था वह अब नहीं रहेगा।

'एल.पी.जी. संकट बढ़ने से कालाबाजारी तेज'

विजय कुमार

अमरीका और इसराईल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमले के बाद पूरी दुनिया में पैट्रोलियम पदार्थों और गैस की किल्लत पैदा हो गई है। दरअसल ईरान ने हमले के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट आफ होर्मुज) को बंद कर दिया है। दुनिया भर को कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति का 20 प्रतिशत हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। देश में एल.पी.जी. की कमी के कारण रैस्टोरैंट कारोबार पर संकट आ गया है और देश के लगभग 10 प्रतिशत ढाबे और रैस्टोरैंट बंद हो गए हैं और कई जगह रैस्टोरैंट्स ने खाने की कीमतें बढ़ा दी हैं तथा अपने मैन्यू में आइटमें कम कर दी हैं। इसी बीच उद्योगों और ढाबों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलैंडर की कीमत बुधवार को एक बार फिर 195.50 रुपए बढ़ाई गई और दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलैंडर की कीमत अब 2078.50 रुपए हो गई है। इससे पहले, 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम के घरेलू एल.पी.जी. के सिलैंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाई गई थी। इसके साथ ही हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एयर टर्बाइनल फ्यूल (ए.टी.एफ.) की कीमतों में भी 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह बढ़ कर 1,04,927 रुपए प्रति किलो लीटर हो गया है। देश भर में पैदा हुई एल.पी.जी. की कमी के कारण इसकी काला बाजारी भी जोरों पर है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर घरेलू रसोई गैस का सिलैंडर 4500 रुपए में बेचा जा रहा है जबकि कमर्शियल सिलैंडर 6000 रुपए तक बिक रहे हैं। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी सुजाता शर्मा ने बताया कि एल.पी.जी. की कालाबाजारी रोकने के लिए 1 अप्रैल को लगभग 2600 छापे मारे गए और लगभग 700 सिलैंडर जब्त किए गए। इस संकट के कारण दुनिया भर में पैट्रोल, डीजल 30 से 50 प्रतिशत महंगा हो गया है लेकिन केंद्र ने पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की बजाय 27 मार्च को पैट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 10 प्रतिशत कम करके इसका बोझ सरकारी तेल कम्पनियों पर डाल दिया है। इसके साथ ही ईरान युद्ध के बाद भारत ने 40 देशों से कच्चा तेल मंगवाना शुरू किया है और इसी कारण अब होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए भारत में सिर्फ 30 प्रतिशत तेल और गैस ही भारत आ रही है जबकि युद्ध से पहले इस मार्ग से भारत 55 प्रतिशत तेल मंगवा रहा था। इसके अलावा भारत ने प्लास्टिक और दवाइयों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पैट्रोकैमिकल्स सहित 40 उत्पादों पर आयात कर में छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले से छोटे उद्योगों में लागत का दबाव कम होगा। देश भर में पैदा हुए रसोई गैस के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और 1 अप्रैल को इसी मुद्दे पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सी.सी.एस.) की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पी.एन.जी. और एल.पी.जी. की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया, उर्वरकों की उपलब्धता का आकलन और भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही कालाबाजारी व जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस स्थिति से निपटने के लिए रसोई गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा आम जनता को भी अब रसोई गैस के विकल्प के तौर पर बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और घरों के अलावा रैस्टोरैंटों और ढाबों में भी इस तरह के चूल्हे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जाने चाहिएं।

माओवाद का खात्मा और साय सरकार की पुनर्वास नीति

उमेश चतुर्वेदी



कभी देश के एक तिहाई हिस्से पर अपनी समानांतर सरकार चलाने वाली माओवादी विचारधारा का क्या आज अंत हो जाएगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय सरकार ने आज ही के दिन को माओवादी आतंकवाद का आखिरी दिन घोषित कर रखा है। ठीक एक हफ्ते पहले यानी 25 मार्च को बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में शीर्ष माओवादी नेता पापा राव के नेतृत्व में 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, तब कहा गया कि राव आखिरी महत्वपूर्ण नक्सली कमांडर हैं और उन्होंने भी हथियार सौंप दिए हैं।

2014 के आम चुनावों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में माओवाद पर लगाम का वादा किया था। तब झीरम घाटी कांड की याद ताजा थी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का तकरीबन समूचे शीर्ष नेतृत्व को माओवादियों ने घेरकर मार डाला था। वैसे खुद नक्सली भी मानते रहे हैं कि उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी सरकारों में खास अंतर नहीं रहा। अलबत्ता कांग्रेस सरकार माओवादी हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाने से बचती रही हैं, जिस तरह बीजेपी की अगुआई वाली सरकारें उठाती रही हैं। बस्तर में छह अप्रैल 2010 को बारूदी सुरंगों के जरिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को उड़ाने के बाद नक्सलियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी गुस्सा था। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने माओवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का मन बना लिया था, लेकिन सिविल सोसायटी के दबाव में यह विचार उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने माओवादियों को कोई रियायत नहीं दी। 2019 में गृहमंत्रालय की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने खुलेआम नक्सलियों को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि या तो वे हथियार डालें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही उन्होंने 31 मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा से देश को मुक्त करने का ऐलान कर दिया।

जिस तरह शीर्ष नक्सली कमांडर या तो मारे गए हैं या फिर उन्होंने हथियार डाले हैं, उससे लगता है कि बीजेपी सरकार का अपना वादा पूरा करने जा रही है। माओवादी विचारधारा के प्रभाव में घर-परिवार, सुख-चैन छोड़कर जंगलों की खाक छानने और सत्ता से जूझने वाले माओवादी युवाओं को मुख्यधारा में लाने में सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों का दबाव ही काम नहीं आया, बल्कि इसमें राज्यों की पुनर्वास योजनाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ ने 2025-26 की अपनी पुनर्वास नीति में हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें उसका %पूना मारगेम% अभियान प्रमुख रहा। इन शब्दों का अर्थ है %नया रास्ता'। इसके तहत दंडकारण्य क्षेत्र के सैकड़ों माओवादी कैडरों को मुख्यधारा में वापस लाने की सफल कोशिश हुई। इसके तहत नक्सलियों की वापसी के बाद उन्हें नई जिंदगी शुरू करने के लिए तत्काल डेढ़ लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी गई, साथ ही उन्हें तीन साल के लिए मासिक वजीफा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना शुरू हुआ। मकसद यह रहा कि हथियार छोड़ने के बाद मुख्यधारा में लौटे माओवादी आत्मनिर्भर जिंदगी बिता सकें। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने हथियार सौंपने वाले माओवादियों को अलग से प्रोत्साहन राशि देने की भी व्यवस्था की। इससे राज्य में माओवादियों के समर्पण में तेजी आई। हथियार छोड़ने वाले माओवादियों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया गया, इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित आवास भी मुहैया कराए गए। इसके साथ ही उन्हें वापसी के बाद भयमुक्त जीवन गुजारने के लिए परिवार की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई।

इसी तरह झारकंड सरकार ने भी माओवादियों को समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए %आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति% बनाई। जिसके तहत समर्पण के बाद माओवादियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उनके कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन्हें रोजगार के साथ ही आवास की व्यवस्था की जाती है। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। झारखंड की इस नीति का उद्देश्य समर्पित नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत हथियार जमा करने पर पूर्व नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि, उन्हें तत्काल पुनर्वास अनुदान और घरेलू सामान के लिए नकद सहायता दी जाती है। साथ ही उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे भविष्य में अपना रोजगार कर सकें। इसके साथ ही उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा व छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जाती है। उन्हें आवास के लिए भूमि या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए जाते हैं। इसी तरह मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों को खेती के लिए प्राथमिकता के आधार पर सोलर पंप और बिजली कनेक्शन भी देने का इंतजाम है। पूर्व नक्सलियों पर चल रहे छोटे मामलों को झारखंड सरकार जहां वापस ले रही है, वहीं गंभीर मामलों में कानूनी सहायता मुहैया करा रही है। कुछ ऐसे ही इंतजाम पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में किए गए हैं।

कभी माओवादियों के डर से बस्तर में सड़कें तक बनाना संभव नहीं था, बिजली पहुंचाना भी कठिन था। झारखंड के भी दूरदराज के इलाके में ऐसा ही हाल था। लेकिन केंद्र सरकार की शह पर राज्य सरकार ने नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्र में भी सड़क, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण कराने में तेजी आई। बस्तर के कुछ इलाके में रेलवे लाइन भी पहुंच गई है। नक्सली इलाके में सड़कें भी बेहतर हो गई हैं। इन कदमों से माओवादी प्रभाव में रहने वाले इलाकों में भरोसा बहाली में मदद मिली। सरकारी योजनाओं के साथ ही सरकार के प्रति भी स्थानीय लोगों का रवैया बदला।

कभी पशुपति से तिरुपति यानी नेपाल से आंध्र तक का जंगली इलाका लाल गलियारे के रूप में विख्यात था। यहां सुरक्षा बलों के लिए भी घुसना आसान नहीं था। इसमें देश के तकरीबन एक तिहाई जिले आते थे। इन जिलों में माओवादी वैचारिकी के असर वाले हथियारबंद दस्तों की सत्ता चलती थी। माओवादी स्कूलों, रेलवे लाइनों, पुलिस थानों, डाकघरों को निशाना बनाते थे। साथ ही वे इलाके की जनता को यह समझाने में कामयाब रहे थे कि मौजूदा व्यवस्था और तंत्र सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण ही कर रहा है। चूंकि विकास की धारा इन इलाकों में माओवादी हथियारबंद दस्तों के अवरोध के चलते बह नहीं पा रही थी, इसलिए अविश्वास का माहौल बढ़ता रहा। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही एक तरफ माओवादियों को उन्हीं की तर्ज में गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ उनके पुनर्वास के साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धारा को भी बहाने की कोशिश तेज की। माओवादी कहते रहे हैं कि सत्ता की राह बंदूक की गोली से निकलती है, बारूद से निकलती है, मोदी सरकार ने कुछ उसी अंदाज में माओवादी सत्ता की राह को बंदूक और बारूद से रोका, लेकिन दूसरी तरफ पुनर्वास अभियान भी जारी रखा। इसमें राज्यों की भूमिका खास रही। चूंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, इसलिए दोनों राज्यों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिसका नतीजा सामने है। कभी पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हिंसक और माओवादी विचारधारा का असर देश के एक तिहाई हिस्से पर रहा। लेकिन अब यह विचारधारा और उसके हथियारबंद अनुयायी निस्तेज नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि वामपंथ की तरह माओवादी विचारधारा भी भारत में कुंद हो गई। नक्सली हिंसा पर लगाम इस लगाम का ही प्रतीक है। वैसे यह भी सच है कि विचारधाराएं कभी नहीं मरतीं, एक विचारधारा के रूप में वह माओवाद भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अब उसके उस तरह प्रतिबद्ध अनुयायी नहीं होंगे, उनकी गोलियों की आवाज और धमक भी नहीं होगी। अगर यह विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े तो शायद ही किसी को एतराज होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर यह विचारधारा जिंदा भी बचती है तो वह लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ेगी, हथियारों के दम पर नहीं।

पुराण दिग्दर्शन ....



सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

आस्तां तावत्! देववृन्द ने गोत्तम जी के तप को भंग करने की ठान ली, परन्तु यह काम सहल न था। बिल्ली के म्याऊं का ठौर पकड़ने के बराबर कठिन सभस्या थी। अप्सरायें जवाब दे बैठीं, कहा कि गोत्तम जी के वर पर हम से भी सुन्दर पतिव्रता धर्मपत्नी विद्यमान है तब वे हमारे हाद भावों के फन्दे में क्यों फँसने लगे!

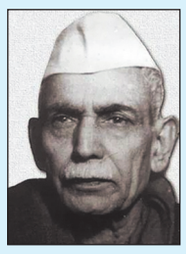
कामदेव ने भी कान छू कर शान्तं पापम् कहते हुये कोरा जबाब दिया कि वहां तो ई जनाब की भी दाल गलती मुश्किल जान पड़ती है। देवसभा में सन्नाटा छा गया, गोत्तम के उग्र स्वभाव का ध्यान करते हुये कोई भी देवता उनके तपोभङ्ग कर सकने की हिम्मत न दिखा सका। विवश होकर स्वयं देवराज को यह काम अपने हाथ में लेना पड़ा। सोचा कि- तपोभङ्ग के हेतुभूत-काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्व्यसनों में से- क्रोध को छोड़ कर और कोई दूसरा शस्त्र गोत्तम जी पर अचूया निशाना न लगा सकेगा, अत, येन केन प्रकारेण गोत्तम जी को क्रुद्ध कर देना चाहिये! बस फिर काम विजय है।

मनोविज्ञानवेत्ता खूब जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में अन्य कई प्रकार के कारणों से भी क्रोध का आवेश हो सकता है, परन्तु जितना जल्दी और जितना भयंकर क्रोध अपनी स्त्री के धर्षण को प्रत्यक्ष देखा कर तत्काल एवं दूध के उफान की भांति आप से बाहिर कर देने वाला-देखने में आता है उतना अन्य किसी कारण से सम्भव नहीं। यही जान कर इन्द्र ने क्रोधोत्पादन के अचूक उपाय, स्त्री घर्षण को ही अपना अमोध अस्त्र बनाया।

अवसर पाकर वह गोत्तम के घर पहुँचे। ऋषि की अनुपस्थिति में-किन्तु जब कि उनका घर पहुंचने का समय निकट था,- ग्रहल्या के घर्षण का अभिनय रचा।

क्रमशः ...

पं. माखनलाल चतुर्वेदी



हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिन्दी जगत के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक व पत्रकार पं. माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को बावई, होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) में हुआ। आपने हिंदी एवं संस्कृत का अध्यापन किया। आप कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक रहे।

पं. माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा नाम हैं, जिसे छोड़कर हम पूरे नहीं हो सकते। उनकी संपूर्ण जीवनयात्रा, आत्मसमर्पण के खिलाफ लड़ने वाले की यात्रा है। रचना और संघर्ष की भावभूमि पर समृद्ध हुई उनकी लेखनी में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का जज्बा न चुका, न कम हुआ। वस्तुत: वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे और कोई मोर्चा ऐसा न था, जहां उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो।

माखनलाल जी ने जब पत्रकारिता शुरू की तो सारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव देखा जा रहा था। राष्ट्रीयता एवं समाज सुधार की चर्चाएं और फिरंगियों को देश बदर करने की भावनाएं बलवती थीं। इसी के साथ महात्मा गांधी जैसी तेजस्वी विभूति के आगमन ने सारे आंदोलन को एक नई ऊर्जा से भर दिया। दादा माखनलाल जी भी उन्हीं गांधी भक्तों की टोली में शामिल हो गए। गांधी के जीवन दर्शन से अनुप्राणित दादा ने रचना और कर्म के स्तर पर जिस तेजी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को ऊर्जा एवं गति दी वह महत्व का विषय है।

इस दौर की पत्रकारिता भी कमोवेश गांधी के विचारों से खासी प्रभावित थी। सच कहें तो हिन्दी पत्रकारिता का वह जमाना ही अजीब था। आम कहावत थी- जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो और सच में अखबार की ताकत का अहसास आजादी के दीवानों को हो गया था। इसी के चलते सारे देश में आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अपने पत्र निकाले। जिनके माध्यम से ऐसी जनचेतना पैदा की कि भारत आजादी की सांस ले सका। वस्तुत: इस दौर में अखबारों का इस्तेमाल एक अस्त्र के रूप में हो रहा था और माखनलाल जी का कर्मवीर इसमें एक जरूरी नाम बन गया था।

हालांकि इस दौर में राजनीतिक एवं सामाजिक पत्रकारिता के समानांतर साहित्यिक पत्रकारिता का एक दौर भी चल रहा था। सरस्वती और उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके प्रतिनिधि के रूप में उभरे। माखनलाल जी ने भी 1913 में प्रभा नाम की एक उच्चकोटि की साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से इस क्षेत्र में सार्थक हस्तक्षेप किया। लोगों को झकझोरने एवं जगाने वाली रचनाओं के प्रकाशन के माध्यम से प्रभा शीघ्र ही हिन्दी जगत का एक जरूरी नाम बन गई। दादा की 56 सालों की ओजपूर्ण पत्रकारिता की यात्रा में प्रताप, प्रभा व कर्मवीर उनके विभिन्न पड़ाव रहे। साथ ही उनकी राजनीतिक वरीयता भी बहुत उंची थी। वे बड़े कवि थे, पत्रकार थे पर उनके इन रूपों पर राजनीति कभी हावी न हो पाई। इतना ही नहीं जब प्राथमिकताओं की बात आई तो मप्र कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता होने के बावजूद उन्होंने सत्ता में पद लेने के बजाए मां सरस्वती की साधना को ही प्राथमिकता दी।

अंगोला से मोदी ने गैस भंडार की कौन सी डील कर ली?

अभिनय आकाश

ईरान अमेरिका जंग शांत होने की जगह आग पकड़ती जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त दो समुद्री ट्रेड रूट्स को लेकर बवाल मचा है। स्टेट ऑफ होर्मूज के पास चल रही जंग से दुनिया पहले ही परेशान थी। लेकिन ईरान के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग में कदम रख दिया है। जिसकी वजह से रेड सी में मौजूद बाब अल मंदेव स्ट्रेट के बंद होने का खतरा भी पैदा हो गया है। आपको बता दें कि बाब अल मदेब स्ट्रेट बंद हो गया तो पूरा यूरोप बर्बाद हो सकता है। यह शिपिंग लिंक ही एशिया को यूरोप से जोड़ता है। बाब अल मंदेब स्टेट भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस से आने वाला ज्यादातर तेल यहीं से भारत पहुंचता है। लेकिन जिस वक्त इन दोनों समुद्री रास्तों को लेकर दुनिया दहशत में है। ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा रणनीतिक और कूटनीतिक दांव खेल दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत अफ्रीका के एक गरीब मगर नेचुरल रिसोर्सेज से भरे देश में ऐसा खेल कर आया है जिसके बारे में एक-एक भारतीय को पता होना चाहिए। भारत ने एक तरफ तो एलपीजी और पेट्रोल की सप्लाई को जारी रखने का शानदार जुगाड़ ढूंढ लिया है। लेकिन इसी के साथ भारत ने दो बेहतरीन ट्रेड रूट्स भी तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत अब किस नए रूट से एलपीजी गैस ला रहा है। भारत ने एलपीजी गैस के लिए अफ्रीका महाद्वीप में एक नया कतर ढूंढ लिया है। भारत की सरकारी कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी सुनानगोल से एलपीजी इंपोर्ट्स शुरू करने जा रही है। अंगोला अफ्रीका का एक गरीब देश जरूर है लेकिन इस देश के पास 11 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के भंडार हैं। भारत पहले से ही अंगोला के साथ थोड़ा बहुत गैस और तेल व्यापार करता रहा है। जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्शन बना रहे। अब यही कनेक्शन भारत के काम आ रहा है।



भारत का 90त्न एलपीजी आयात ठप होने की कगार पर है। दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। स्थिति कंट्रोल में रहे उसके लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। तमाम देशों से बातचीत चल रही है। पर्दे के पीछे ईरान से बातचीत कर हॉर्मूज से धीरे-धीरे गेट खुलवाकर भारत के जहाज निकलवाए जा रहे हैं। लेकिन क्या तीन से चार चार से पांच जहाजों का आना काफी है? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ युद्ध थमता नजर नहीं दिख रहा है बल्कि और भी भयानक होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के करोड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे या फिर भारत ने इस संकट का कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जो दुनिया को हैरान करे। क्योंकि अब भारत की नजरें खाड़ी देशों से हटकर एक नए और अनजान दोस्त पर आकर टिक गई है। दरअसल जब हॉर्मूज के दरवाजे बंद हुए तो भारत ने अपने पुराने दोस्तों और नए रास्तों की ओर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया।

भारत ने अर्जेंटीना से लेकर अमेरिका और नॉर्वे से लेकर रूस तक से गैस मंगानी शुरू कर दिया। लेकिन इसमें दूरी और समय बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका से गैस आने में हफ्तों लग जाते हैं। जब देश में मांग चरम पर है। इतनी दूरी से आने वाली सप्लाई ऊंट के मुंह में जीरे जैसा सामान है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है। तो ऐसे में सरकार की पूरी मशीनरी इस कोशिश में जुटी है कि किसी भी कीमत पर सप्लाई चेन टूटने ना पाए। कतर और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक ठिकानों से संपर्क कटने के बाद भारत की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल अब ग्लोबल मार्केट में एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रही हैं जो संकट के इस समय में भारत की ढाल बन सके। और यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय। एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ तेल और हीरों के लिए जाना जाता था। लेकिन अब वो भारत की रसोई का रखरखाव करने जा रहा है। इस पूरे संकट के बीच एंट्री हुई है अफ्रीका के दिग्गज देश अंगोला की। जी हां, वही अंगोला जो नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है।

भारतीय ऊर्जा कंपनियां अब अंगोला की सरकारी कंपनी सोनान गोल के साथ हाई लेवल बातचीत कर रही हैं। और यह डील साधारण नहीं होगी। अगर यह बातचीत सफल हो जाती है तो अंगोला भारत को कुकिंग गैस सप्लाई करने वाला पहला मध्य अफ्रीकी देश बन जाएगा। लेकिन अंगोला ही क्यों? इसका जवाब छिपा है भूगोल और गणित। एक्सपर्ट का मानना है उत्तरी अमेरिका के मुकाबले अंगोला से भारत तक गैस पहुंचने में 10 से 15 दिन कम लगेंगे। यह 15 दिन भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। अंगोला के पास 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वित्त वर्ष 2025 में अंगोला ने भारत को पहले ही 924 मिलियन की एलएजी सप्लाई की है। अब इसी दोस्ती को एलपीजी तक ले जाने की तैयारी है। यह सिर्फ एक बिजनेस रील नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक जीत है। जहां एक तरफ हॉर्मूज में बारूद बरस रहा है। हॉर्मूज का रास्ता बंद पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने हजारों मील दूर अफ्रीका में अपनी ऊर्जा सुरक्षा का नया किला तैयार कर लिया है। 8000 किमी की दूरी है हवाई। तो सोचिए कितना डिस्टेंस पड़ रहा है। भारत और अंगोला का रिश्ता आज का नहीं है। इसकी जड़े 1985 में जमी थी। आज अंगोला में करीब 8000 भारतीय वहां की अर्थव्यवस्था की रीड बने हुए हैं। चाहे वो रिटेल हो, खेती हो या हॉस्पिटिलिटी। भारत आज अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच 4.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी होता है। हम उनसे सिर्फ गैस ही नहीं ले रहे हैं बल्कि हम उन्हें डिफेंस दवाएं कृषि तकनीक भी दे रहे हैं। हम साथ मिलकर अंतरिक्ष और माइनिंग के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहे हैं।

हालात तो यही बता रहे हैं कि अब भारत में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। हालांकि नॉर्मल स्थिति करने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों तक सप्लाई भी पहुंचा रही है। लेकिन संकट खड़ा ना हो। यही वजह है कि मोदी सरकार की डायवर्सिफिकेशन की नीति रंग ला रही है क्योंकि हॉरमूज बंद होने से भारत पर जो संकट खड़ा हो सकता है अंगोला उसका मरहम बनता दिख रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो अगर हौसला और विज़न सही हो तो रास्ते समंदर के बीच से ही निकल आते हैं।

आज का इतिहास

1873 यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया का पहला केनेल क्लब स्थापना की गई।
1887 सुसाना मेडोरा साल्टर पहली अमेरिकी महिला महापौर बानी।
1905 हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में भूकंप से करीब 20000 लोगों की जाने गईं थी।
1909 फुटबॉल टीम स्पोर्ट क्लब इंटरनेशनल पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में स्थापित किया गया।
1916 अमेरिकी सीनेट में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने पर सहमति जताई।
1929 ब्यूजु में रोमानिया के नजदीक एक रेलगाड़ी के पटरी से उतरने पर 20 लोग मारे गए और 59 घायल हुए।
1932 वैजिस्लाव मरिन्कोविक यूगोस्लाविया के प्रधान मंत्री बने।
1945 द्वितीय विश्व युद्ध-अमेरिकी सेना ने तीन दिनों की लड़ाई के बाद जर्मन शहर कासेल पर कब्जा कर लिया।
1949 उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन (नाटो) की स्थापना हुई जो शीतयुद्ध के शुरुआती दौर का नतीजा थी।
1960 अफ्रीकी देश सेनेगल ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने की घोषणा की।
1960 सेनेगल ने फ्रांस के साथ बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो देश की आजादी के लिए अग्रणी था।
1968 अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग, जूनियर की मेम्फिस, टेनेसी में हत्या कर दी गई थी।
1969 सर्जन डेंटन कोलेई और डोमिंगो लिओटा ने पहले कुल कृत्रिम हृदय को प्रत्यारोपित किया।
1973 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आधिकारिक तौर पर समर्पित किया गया था, भवन परिसर के जुड़वाँ के दूसरे पूरा होने के लगभग एक साल बाद।
1976 नॉरडोम सिहानौक को कंबोडिया के नेता की भूमिका से अलग किया गया और उसे खमेर रूज ने गिरफ्तार कर लिया।
1977 न्यू होप, जॉर्जिया में एक राजमार्ग पर दक्षिणी एयरवेज की उड़ान 242 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 72 लोग मारे गए।
1979 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फ़ाँसी दी गई।
1984 अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने रासायनिक हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के लिए कहा।
1988 एरिज़ोना के गवर्नर इवान मेखम को महाभियोग के मुकदमे में दोषी ठहराए जाने के बाद पद से हटा दिया गया था।
1990 हांगकांग का वर्तमान ध्वज सातवें राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस के तीसरे सत्र के उपनिवेशवाद के बाद अपनाया गया था।

मुश्किल के समय भारत बना पड़ोसियों के लिए संकटमोचक

नीरज कुमार दुबे

दक्षिण एशिया की राजनीति में अचानक आया यह मोड़ किसी भूचाल से कम नहीं है। कुछ महीने पहले तक भारत को घेरने की साजिश रचने वाले पड़ोसी देश आज उसी भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। ईरान युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट ने पूरे क्षेत्र की असलियत उजागर कर दी है। जो देश कभी इंडिया आउट का नारा लगा रहे थे, आज वही भारत से तेल और गैस की मदद मांग रहे हैं। यह सिर्फ कूटनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का निर्णायक पल है।

सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कच्चे तेल का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा एशिया के देशों के लिए होता है। ईरान युद्ध ने इस जीवनरेखा को झकझोर दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश ऊर्जा निर्भरता के दलदल में फंस गए हैं। भारत भी आयात पर निर्भर है, लेकिन उसकी रणनीतिक तैयारी और संतुलित कूटनीति ने उसे संकट में भी मजबूत बनाए रखा है। ईरान ने भारत को मित्र मानते हुए तेल और रसोई गैस के जहाजों को रास्ता दिया, जो भारत के लिए बड़ी राहत साबित हुआ।

लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। भारत ने सिर्फ अपनी जरूरतों की चिंता नहीं की, बल्कि अपने पड़ोसियों को संकट से निकालने का बीड़ा उठाया। यही है भारत की पड़ोस पहले नीति का असली चेहरा, जो केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है।

हम आपको बता दें कि युद्ध से उपजे संकट का बांग्लादेश सबसे बड़ा शिकार बना है। अपनी जरूरत का 95 प्रतिशत तेल और तीस प्रतिशत गैस आयात करने वाला यह देश अब अंधेरे में डूब रहा है। बिजली कटौती, उद्योगों का ठप होना और विश्वविद्यालयों का बंद होना इस बात का सबूत है कि ऊर्जा संकट किसी देश की रीढ़ कैसे तोड़ सकता है। कपड़ा उद्योग, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की जान है, इस समय डीजल की कमी से जूझ रहा है।

ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने भारत की ओर रुख किया और भारत ने बिना देरी किए मदद का हाथ बढ़ाया। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पाइपलाइन के जरिए डीजल की आपूर्ति तेज कर दी गई। हजारों टन ईंधन भेजा गया और आगे भी आपूर्ति जारी है। हम आपको याद दिला दें कि यह वही बांग्लादेश है जहां हाल ही में भारत विरोधी माहौल चरम पर था और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही थीं। लेकिन संकट ने उसे सच्चाई दिखा दी कि असली सहारा कौन है।



मालदीव का मामला और भी दिलचस्प है। एक साल पहले तक भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा जहरीली भाषा बोलने वाले इस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु आज भारत को विश्वसनीय साथी बता रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपति मुइज्जु ने सत्ता में आते ही भारतीय सैनिकों को देश से बाहर कर दिया था और चीन की तरफ झुकाव दिखाया था। लेकिन जैसे ही ऊर्जा संकट और पर्यटन पर असर पड़ा, पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। अब पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के लिए मालदीव को वही भारत याद आ रहा है।

श्रीलंका की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। 2022 के आर्थिक पतन की यादें अभी ताजा हैं। उस समय चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की कीमत उसे भारी पड़ी थी। अब फिर वही स्थिति बन रही है। ऊर्जा जरूरत का साठ प्रतिशत आयात करने वाला श्रीलंका एक महीने से ज्यादा का भंडारण भी नहीं रख पाता। उसे ईंधन के दाम तैंतीस प्रतिशत तक बढ़ाने पड़े हैं। ऐसे समय में भारत ने एक बार फिर पहला सहायक बनकर दिखाया। हजारों टन पेट्रोल और डीजल तुरंत भेजा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से भारत का आभार जताया। यह केवल सहायता नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत है कि संकट के समय कौन साथ खड़ा होता है।

दक्षिण एशिया के इस बदलते परिदृश्य में नेपाल का जिक्र भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह वह पड़ोसी है जहां भारत की मदद लगातार और बिना किसी शोर के पहुंच रही है। ऊर्जा संकट के इस दौर में भारत ने नेपाल को ईंधन और आवश्यक आपूर्ति की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है। दरअसल, हिमालयी भूगोल और सीमित संसाधनों के कारण नेपाल पूरी तरह बाहरी आपूर्ति पर निर्भर है और ऐसे समय में भारत की स्थिर सप्लाई लाइन उसके लिए जीवनरेखा बनी हुई है। यह संबंध केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भरोसे और पारस्परिक सहयोग का प्रतीक है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने पड़ोसियों को संकट में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों।

देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व बेहद गहरा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि दक्षिण एशिया की ऊर्जा सुरक्षा की धुरी वही है। साथ ही यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधी चुनौती है। जिन देशों ने चीन के भरोसे अपनी नीतियां बनाई थीं, वह अब भारत की ओर लौट रहे हैं। इसके अलावा, भारत ने मानवीय सहायता को रणनीतिक हथियार में बदल दिया है।

रणनीतिक रूप से देखें तो यह भारत के लिए सुनहरा मौका है। ऊर्जा आपूर्ति के जरिए भारत न केवल अपने पड़ोसियों को स्थिर कर रहा है, बल्कि उनके भीतर अपनी विश्वसनीयता भी मजबूत कर रहा है। यह भविष्य में सुरक्षा, व्यापार और राजनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोलेगा।

बहरहाल, यह साफ है कि भाषण और नारे अपनी जगह हैं, लेकिन भूगोल और जरूरतें अपनी जगह। संकट के समय वही देश मायने रखता है जो मदद कर सके। और इस परीक्षा में भारत न केवल पास हुआ है, बल्कि पूरे क्षेत्र का केंद्र बनकर उभरा है। यही नया दक्षिण एशिया है, जहां भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि जीवनरेखा बन चुका है।

खासतौर पर इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अगर किसी एक नेतृत्व की छाप सबसे स्पष्ट दिखती है, तो वह है प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर रणनीति और दूरदर्शिता के साथ फैसले लिए हैं। जहां एक तरफ पड़ोसी देश कभी भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे, वहीं आज वही देश भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मान रहे हैं। यह बदलाव अपने आप नहीं आया, बल्कि लगातार संवाद, सहायता और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है।

मोदी की नीति ने यह साबित कर दिया है कि सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन ही असली कूटनीति है। आज भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि संकट में भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है और यह उपलब्धि सीधे तौर पर मोदी की रणनीतिक सोच और निर्णायक नेतृत्व का नतीजा है।

ऊर्जा संकट में भी आत्मविश्वास कायम रहने का क्या है राज ?

आलोक मेहता

जर्मनी से एक पत्रकार मित्र ने फोन करके जानना चाहा कि युद्ध और वैश्विक तेल ऊर्जा संकट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चिंतित होने के बजाय आत्मविश्वास दिखाने और जनता को भी विचलित न होने के लिए कहने का राज क्या है? वैसे आधिकारिक दावे के लिए मैंने उन्हें सरकारी अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेने को कहा लेकिन उनके आग्रह पर मैंने भारत की ऊर्जा क्षमताओं की कुछ पृष्ठभूमि तथा हाल के वर्षों में तेल, पेट्रोल, गैस आदि के लिए हुई तैयारियों की अपनी जानकारियों को उनसे शेयर किया। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत विश्व के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है।

ऐसे में खाड़ी देश - जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत आदि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार रहे हैं। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां पिछले कई दशकों से इन देशों के साथ तेल आपूर्ति, खोज और निवेश के समझौते करती रही हैं।

आज भारत केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि खाड़ी देशों के साथ निवेशक, साझेदार और ऊर्जा रणनीतिक सहयोगी बन चुका है। भारत ने पिछले एक दशक में ऊर्जा कूटनीति को नए स्तर पर पहुंचाया है। वहीं अफ्रीका में भारत ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।

1970-90 के दशक में भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध मुख्यत: 'तेल खरीद' तक सीमित थे। भारत कच्चा तेल खरीदता था, निवेश या उत्पादन में भागीदारी बहुत कम थी। भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति सीमित थी। वर्ष 2000 के बाद भारत ने रणनीति बदली और ऊर्जा सुरक्षा के लिए विदेशों में तेल क्षेत्रों में हिस्सेदारी लेना शुरू किया। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने विदेशों में निवेश बढ़ाया।

मोदी सरकार आने के बाद 2014 से 2026 के बीच रणनीतिक साझेदारी का नया दौर शुरू हुआ। अब संबंध केवल खरीद तक सीमित नहीं रहे बल्कि निवेश, भंडारण और गैस के संयुक्त उत्पादन के काम होने लगे। संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऐतिहासिक समझौते हुए। 2018 में भारतीय कंपनियों को ऑयलफील्ड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली। यह पहला मौका था जब भारत को खाड़ी में उत्पादन में भागीदारी मिली। यह समझौता 40 वर्षों के लिए है। भारत और खाड़ी देशों के बीच कुल मिलाकर 20 से अधिक प्रमुख ऊर्जा समझौते हैं।

इन समझौतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निर्णायक रही। खाड़ी देशों के साथ राजनीतिक विश्वास बढ़ाया। पिछले एक दशक 2014-2025 में लगभग 35-45 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल विदेशी ऊर्जा निवेश हुआ। अफ्रीका में 20-25 अरब डॉलर, खाड़ी देशों में 10-15 अरब डॉलर और एलएनजी तथा गैस प्रोजेक्ट्स में 10 अरब डॉलर का निवेश हुआ।

वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के वर्तमान दौर में भारत एक संतुलित कूटनीतिक रणनीति अपना रहा है। एक ओर भारत की निजी और सार्वजनिक कंपनियां अमेरिका जैसे विकसित देशों में निवेश बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को भी मजबूती से बनाए रखा गया है। हाल ही में रिलायन्स इंडस्ट्रीज द्वारा अमेरिका में रिफाइनरी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की योजनाओं ने इस संतुलन को और स्पष्ट किया है। यह संकेत है कि भारतीय कंपनियां अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में प्रवेश कर रही हैं।

पाकिस्तान से दूरी बनाते तारिक रहमान

सुबीर भौमिक

बांग्लादेश ने विगत 26 मार्च को 'नरसंहार दिवस' के रूप में मनाया और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस अवसर पर 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गये 'क्रूर और सुनियोजित' हत्याकांडों की कड़ी आलोचना करते हुए दुनिया का ध्यान इस ओर दिलाते हुए उसे नरसंहार की मान्यता दिलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा कि स्वतंत्रता प्रेमी बांग्लादेश के इतिहास में 25-26 मार्च, 1971 का दिन 'सबसे शर्मनाक और क्रूर दिनों' में से एक था। उन्होंने कहा, उस अंधेरी रात में पाकिस्तानी कब्जे वाली सेना ने 'ऑपरेशन सर्चलाइट' के नाम पर निहत्थे बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ इतिहास के सबसे जघन्य नरसंहारों में से एक को अंजाम दिया था। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय, पिलखाना और राजारबाग पुलिस लाइंस सहित कई जगहों पर शिक्षकों, बुद्धिजीवियों व निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलायीं, जिससे अनेक लोग मारे गये थे।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 25 मार्च, 1971 की रात से शुरू हुई हत्याओं को 'पूर्व नियोजित नरसंहार' बताया और राष्ट्र से शहीदों के बलिदान को याद रखते हुए उन्हें गहरी श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री रहमान की इन टिप्पणियों ने स्वाभाविक ही पाकिस्तान को आहत किया, जो अगस्त, 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था। दरअसल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने 18 महीनों के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ संबंधों को काफी हद तक गर्मजोशी दी और उनके कार्यकाल में दोनों तरफ से उच्चस्तरीय कूटनीतिक और सैन्य यात्राएं भी हुईं।

प्रधानमंत्री रहमान द्वारा 1971 की घटनाओं को नरसंहार कहे जाने से आहत होकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को 'जटिल और विभिन्न तरह की व्याख्याओं के लिए खुला' बताकर मामले की गंभीरता को कम करने की कोशिश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक मीडिया



ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान 1971 की घटनाओं को जटिल मानता है और विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुला समझता है। इस पर रचनात्मक संवाद, आपसी सम्मान और ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता के प्रति साझा प्रतिबद्धता आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश की जनता के साथ आपसी सम्मान और रचनात्मक सहयोग पर आधारित भविष्य-दृष्टि वाले संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, जो जन-जन के संबंधों, आर्थिक सहयोग व क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पाकिस्तान द्वारा किये गये 1971 के नरसंहार को वैश्विक चर्चा में लाने की जो पहल की, उसे भारत की तरफ से स्वाभाविक ही मजबूत समर्थन मिला। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम सभी 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तान द्वारा किये गये भयानक अत्याचारों से अवगत हैं। उस नरसंहार में लाखों निर्दोष बांग्लादेशियों की योजनाबद्ध हत्या और महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर यौन अपराध शामिल थे। उन्होंने आगे जोड़ा, उस अत्याचार के कारण लाखों लोग देश छोड़कर भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। उन अत्याचारों ने विश्व की अंतरात्मा को झकझोर दिया, लेकिन पाकिस्तान आज भी उन अपराधों से इनकार करता है।

हम न्याय की मांग में बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। भारत के लिए प्रधानमंत्री रहमान का यह रुख संतोषजनक है, क्योंकि भारत लंबे समय से पाकिस्तान की सेना को दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण में सबसे बड़ी बाधा मानता रहा है। नयी दिल्ली इसे इस संकेत के रूप में देख रही है कि बांग्लादेश की रहमान सरकार भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेगी। कुछ भारतीय अधिकारियों का यह भी मानना है कि बांग्लादेश की नयी सरकार 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना को अपनी राजनीति का आधार बनाने की कोशिश कर सकती है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है, तो ढाका नयी दिल्ली के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेगा।

गौरतलब है कि 1948 में हुए संयुक्त राष्ट्र नरसंहार सम्मेलन और 1951 में उसके अनुमोदन के बाद अब तक केवल तीन ही नरसंहारों-1975-79 के कंबोडिया में पोल पॉट के शासन के दौरान हुए नरसंहार, 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार और 1995 के बोस्निया के स्रेब्रेनिका में हुए नरसंहार को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है, और उन्हें अंजाम देने वालों पर मुकदमे चले हैं। बांग्लादेश लंबे समय से 1971 के नरसंहार को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलाने की मांग करता रहा है। वर्ष 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद यह मांग और तेज हुई।

शेख हसीना के प्रधानमंत्री काल में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने वाली एक युवा मंत्री तराना हलीम थीं, जो राजनीति में आने से पहले एक चर्चित अभिनेत्री और वकील थीं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी सेना द्वारा अंजाम दिये गये 1971 के नरसंहार को मान्यता देकर संयुक्त राष्ट्र अपनी छवि सुधार सकता है। इस संबंध में उन्होंने तीन मुख्य तर्क दिये थे। पहला तर्क यह था कि मार्च से दिसंबर, 1971 तक पाक सेना और उसके सहयोगियों द्वारा मारे गये लोगों की संख्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य नरसंहारों से कहीं अधिक थी-आठ महीनों में लगभग 30 लाख बंगालियों की हत्या की गयी थी। वर्ष 1971 का नरसंहार केवल अंधाधुंध हत्याओं तक सीमित नहीं था, बल्कि बुद्धिजीवियों की लक्षित हत्या, लगभग तीन लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और व्यापक आगजनी भी उसमें शामिल थी। और तीसरा तर्क यह कि उस नरसंहार को पाकिस्तान की मिलिशिया ने नहीं, बल्कि नियमित सेना ने अंजाम दिया था। फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने 1971 के इस नरसंहार को मान्यता क्यों नहीं दी? तराना हलीम के अनुसार, इसका कारण पश्चिमी शक्तियां, विशेषकर अमेरिका है, जो रणनीतिक कारणों से पाकिस्तान की सेना को अपना सहयोगी मानता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश की नयी सरकार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में कितनी मजबूती से उठायेगी। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में उसके सामने अन्य चुनौतियां भी हैं, लेकिन अवामी लीग के राजनीतिक परिदृश्य से बाहर होने के बाद बीएनपी खुद को 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत का वाहक बताने की कोशिश कर सकती है, खासकर तब जब उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी है, जिसने 1971 में पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था।

तमिलनाडु में मामला उतना भी सीधा नहीं

आर राजगोपालन

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है, जहां 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला राज्य के करीब छह करोड़ मतदाता करेंगे। लगता है कि इस बार 234 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव के नतीजे एक नया राजनीतिक आश्चर्य और मोड़ लेकर आएंगे। नए जनादेश के तहत सबसे बेहतरीन तालमेल वाले नए चेहरे ही आगामी चार मई को चुनकर अगले पांच वर्षों के लिए विधायक बनेंगे। पिछले 70 वर्षों से, बारी-बारी से या तो द्रमुक ने या फिर अन्नाद्रमुक ने ही राज्य पर राज किया है। अन्नाद्रमुक, विजय के टीवीके जैसी विपक्षी पार्टियों की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जबकि एमके स्टालिन की द्रमुक को सबसे ज्यादा सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है।

तमिलनाडु में चुनाव का मुख्य मुद्दा नशीले पदार्थ हैं। द्रमुक को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दल अवैध व विदेशी शराब की तस्करी, विश्वविद्यालयों में दुष्कर्म और कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। सही सूचना के लिए जनता ने अब सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लाइव रिपोर्टिंग देखना शुरू कर दिया है, जो राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ है।

द्रमुक और अन्नाद्रमुक की जड़ें तमिलनाडु के हर गांव में फैली हुई हैं, लेकिन भाजपा या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ऐसा नहीं है। एक नई राजनीतिक पार्टी, टीवीके (तमिलगा वेत्री कड़गम-तमिल विजय पार्टी) का गठन हुआ है, जिसे तमिल सिनेमा के 'सुपर हीरो' जोसेफ विजय ने शुरू किया है। इसलिए पहली बार, तमिलनाडु में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।

विजय के राजनीति में आने से राज्य के ईसाई समुदाय को रणनीतिक बढ़ावा मिला है। अल्पसंख्यकों का वोट बैंक एक 'दोधारी तलवार' जैसा है। पहली बार अल्पसंख्यकों के वोट द्रमुक से हटकर टीवीके की तरफ जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि टीवीके कुल वोटों में से 20-25 प्रतिशत पर कब्जा कर सकती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि विजय के प्रशंसकों की संख्या बहुत ज्यादा है।

तमिलनाडु में भाजपा को मोदी-अमित शाह की जोड़ी



से एक बड़ा बढ़ावा मिला है। द्रविड़ प्रदेश में राजग को अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी पलानीस्वामी से लाभ मिलेगा। जयललिता के जीवनकाल में अन्नाद्रमुक के चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर का जिक्र किया गया था। तमिलनाडु में कमल का चुनावी निशान भी काफी लोकप्रिय है। पिछली विधानसभा में भाजपा के चार विधायक थे।

तमिलनाडु में कांग्रेस एक परखी हुई और राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी है। द्रमुक गठबंधन में इसकी मौजूदगी, ज्यादा धर्मनिरपेक्ष वोट हासिल करने के लिए एक नैतिक संबल का काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि विजय द्वारा टीवीके की शुरुआत किए जाने और करूर रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के टीवीके के करीब आने की घटनाओं ने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। करूर घटना के बाद पिछले छह महीनों में, राहुल गांधी टीवीके के और करीब आने के लिए उत्सुक रहे हैं। लेकिन द्रमुक ने इसे पहले ही भांप लिया। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से एमके स्टालिन ने कांग्रेस को द्रमुक के नए गठबंधन, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) से बाहर निकलने से रोक दिया। सीमन 'नाम तमिलर काची' (एनटीके) के नेता हैं। एनटीके लंबे समय से लिट्टे नेता प्रभाकरन की समर्थक रही है और 'तमिल ईलम' के मुद्दे को उठाती रही है। इस चुनाव में वह अकेले ही लड़ रही है। उनके पास आठ प्रतिशत का निश्चित वोट बैंक है, जिसमें वे लोग शामिल हैं, जो 'तमिल राष्ट्रवाद' का समर्थन करते हैं। द्रमुक की चुनावी शैली मुख्य रूप से भाजपा-विरोधी बातों और मोदी व शाह पर की जाने वाली टिप्पणियों पर केंद्रित रहती है। वे 'सनातन धर्म' के खिलाफ नफरत भरे भाषण देते हैं और इसकी तुलना डेंगू व कोरोना जैसी बीमारियों से करते हैं। एमके स्टालिन की रणनीति मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने पर आधारित है। द्रमुक को इस बात का अंदाजा है कि विजय ईसाई वोट अपने पाले में कर लेंगे। मुस्लिम वोटर भी विजय की तरफ झुक सकते हैं। इसके अलावा, कुछ बाहरी कारक भी हैं, जैसे कि चुनाव के लिए पैसे का इंतजाम और देर रात मतदाताओं के बीच नकदी बांटना। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 'लॉटरी किंग' मार्टिन सभी पार्टियों को फंड दे रहे हैं। चुनावी घोषणापत्र अब मजाक का विषय बन गए हैं-फ्रिज, लैपटॉप, ग्राइंडर, व्हीलचेयर, और छात्रों व किशोरों के लिए मुफ्त वाईफाई इंटरनेट की सुविधा देने जैसे वादे किए जा रहे हैं। विजय तो मुफ्त की चीजें देने के मामले में और भी आगे निकल गए हैं। इसके अलावा, अन्नाद्रमुक से निकाले गए नेताओं पर द्रमुक दांव लगा रही है और उन्हें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है।

पिछले चुनावों में, जब मुकाबला मुख्य रूप से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच था, तब जीत हासिल करने में ईसाई और मुस्लिम समुदायों के समर्थन ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन टीवीके के चुनावी मैदान में प्रवेश और जोसेफ विजय के 'ईसाई' होने की पहचान की वजह से, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों का एक हिस्सा उनकी तरफ जाने की उम्मीद है। चूंकि, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुख्य रूप से द्रमुक और टीवीके में से किसी एक को चुनने वाले हैं, ऐसे में हिंदू वोट (जिनमें कोनार, मुक्कुलाथोर, मुथराईयर और अनुसूचित जातियां शामिल हैं) निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सभी पार्टियों के चुनावी अभियानों और तमिलनाडु के मिजाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि राज्य में मुकाबला कड़ा होगा। नशीले पदार्थ और अवैध शराब मुख्य चर्चा का विषय होंगे। अगले दो हफ्तों तक जोशीले और भड़काऊ भाषण, नुक्कड़ सभाएं और रोड शो देखने को मिलेंगे। चतुष्कोणीय मुकाबले में जीत का अंतर एक हजार मतों से भी कम रहने की संभावना है। कई जनमत सर्वेक्षण मिश्रित नतीजों का अनुमान लगा रहे हैं। तमिलनाडु में सत्ता-विरोधी लहर के चलते, कुछ लोग 'त्रिशंकु विधानसभा' की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं।

युद्ध के चलते दुनिया भर में 'ऊर्जा लॉकडाऊन' का डर!

रजनीश कपूर

विश्व आज एक नए संकट के कगार पर खड़ा है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए अमरीका-इसराईल और ईरान युद्ध ने मात्र 4 सप्ताह में वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', जिससे दुनिया के 20 प्रतिशत तेल और एल.एन.जी. का परिवहन होता है, प्रभावी रूप से बंद हो गया है। ईरान के साऊथ पार्स गैस फील्ड और कतर के रास लाफान एल.एन.जी. प्लांट पर हमलों से वैश्विक उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की कमी आई है, जिसकी मुरम्मत में वर्षों लग सकते हैं। तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, जबकि भारत जैसे आयात-निर्भर देशों में ईंधन, एल.पी.जी. और बिजली की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में 'ऊर्जा लॉकडाऊन' की चर्चा जोर पकड़ रही है। एक ऐसी स्थिति, जिसमें ईंधन राशनिंग, बिजली कटौती और औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लग सकता है, ठीक कोविड जैसी आपात स्थिति की तरह। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आई.ई.ए.) के प्रमुख फितह बिरोल ने इसे 'मेजर, मेजर थ्रैट' बताया है। होर्मुज बंद होने से न केवल तेल, बल्कि उर्वरक, हीलियम और सल्फर की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जो खाद्य उत्पादन और ए.आई. तकनीक तक को प्रभावित कर रही है। बंगलादेश ने पहले ही ईंधन राशङ्क्षनग लागू कर दी है। श्रीलंका में अनिवार्य ऊर्जा अवकाश की घोषणा हुई है। भारत में भी पैट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, एल.पी.जी. सिलैंडर की आपूर्ति अनिश्चित है और बिजली संयंत्रों में कोयला-गैस का संकट गहरा रहा है। यदि युद्ध लंबा चला तो 'ऊर्जा लॉकडाऊन' वास्तविकता बन सकता है। यानी उद्योग बंद, परिवहन सीमित और घरेलू बिजली पर पाबंदी। यह न केवल मुद्रास्फीति बढ़ाएगा, बल्कि विकास दर को 1-2 प्रतिशत तक घटा सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि होर्मुज 2-3 महीने और बंद रहा तो वैश्विक मंदी अनिवार्य हो जाएगी। लेकिन संकट के बीच आशा की किरण भी दिख रही है। शांति वार्ता की संभावना बन रही है और इसमें पाकिस्तान की भूमिका अचानक केंद्र में आ गई है। खबरों के अनुसार, अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर ग़लीबाफ के बीच इस्लामाबाद में संभावित शिखर वार्ता की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान ने 15 प्वॉइंट प्रस्ताव अमरीका की ओर से ईरान तक पहुंचाया है, जिसमें होर्मुज खोलने, यूरेनियम संवर्धन सीमा और मुआवजे जैसे मुद्दे शामिल हैं। सवाल उठता है कि क्या युद्धविराम संभव है? कूटनीतिक विशेषज्ञों की राय विभाजित है। कुछ का मानना है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता एक 'टर्निंग प्वॉइंट' साबित हो सकती है क्योंकि दोनों पक्ष थक चुके हैं। तेल की महंगाई के चलते अमरीका को घरेलू आर्थिक दबाव और इसराईल को क्षेत्रीय विस्तार की सीमा का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमरा रही है। वाशिंगटन इंस्टीच्यूट और स्टिमसन सैंटर के विश्लेषकों का कहना है कि यह युद्ध 'कोई स्पष्ट विजेता' नहीं देगा। इसराईल के हमलों से ईरान की ऊर्जा सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनकी मुरम्मत में वर्षों लगेंगे। ईरान की ओर से जवाबी हमले अभी भी जारी हैं। यदि युद्धविराम हो भी गया तो भी 'दूसरे चरण' के मुद्दे जैसे कि परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और मुआवजा आदि बने रहेंगे। यदि पाकिस्तान सफल हुआ तो भारत को फायदा होगा, क्योंकि हमारा 60 प्रतिशत तेल आयात मध्य-पूर्व से आता है लेकिन भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रणनीतिक भंडार बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा को तेज करना और रूस-मध्य एशिया से आयात विविधीकरण करना। 'ऊर्जा लॉकडाऊन' से बचने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। लेकिन यदि युद्ध जारी रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत जैसे विकासशील देशों को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, न केवल संकट प्रबंधन के लिए, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए भी। यह संकट हमें याद दिलाता है कि युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि ऊर्जा पाइपलाइनों और आर्थिक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी लड़ा जाता है।

स्विट्जरलैंड से नक्सलियों के पास पहुंचा गोल्ड

■ नीष कुंजाम बोले- माओवादियों का जल-जंगल-जमीन बचाने का नहीं लाल किला पर लाल झंडा गाड़ना था लक्ष्य



जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा के पूर्व रूख और आदिवासी लीडर मनीष कुंजाम का कहना है कि नक्सलियों के पास से बरामद हुआ सोना स्विट्जरलैंड से आया है। उन्होंने कहा कि पैसे तो इन्हें हमारे यहां के ही लोग देते थे, लेकिन सोना विदेश के बैंकों से आया है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, इतने सालों तक नक्सली जल-जंगल-जमीन की लड़ाई की बात किए। लेकिन जल-जंगल-जमीन को बचाना इनका लक्ष्य नहीं था। बल्कि ये लोग लाल किले पर लाल झंडा गाड़ना चाहते थे। नक्सली यहां के पहाड़, जंगल और नदियां बचाना नहीं चाहते थे। मनीष कुंजाम ने सरेंडर किए नक्सलियों से सवाल करते पूछा कि अलग-अलग जिले में माइनिंग शुरू करने सैकड़ों ग्रामीणों ने लंबे समय तक आंदोलन किया। ये ही आंदोलन के लिए भेजा करते थे। विरोध और आंदोलन के बाद भी अब आमदई खदान कैसे शुरू हुआ? रावघाट खदान कैसे शुरू हो गया? रेट बढ़ गया। बाद में इनकी वसूली शुरू हो गई। मनीष कुंजाम ने कहा कि, हमारे पास इसका सबूत है। जिस दिन जरूरत रही सबूत दिखाएंगे। अलग-अलग एजेंट्स नक्सलियों तक करोड़ों रुपए पहुंचाते थे। जब उनके पास पैसे पहुंचे, पैसे मिलते ही खदान शुरू हो गया। यदि समय पर उन्हें पैसे नहीं मिलते थे तो वे कोई घटना कर देते थे। दरअसल, 31 मार्च को बीजापुर जिले में 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इनके पास से 7 किलो से ज्यादा गोल्ड भी पुलिस ने बरामद किया था। जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इससे पहले जगदलपुर में भी सरेंडर किए नक्सलियों के पास से भी डेढ़ किलो गोल्ड बरामद किया गया था।

मनेन्द्रगढ़ में वन विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल

एमसीबी। मनेन्द्रगढ़ में एमसीबी जिले के जनकपुर में वन विभाग की बुलडोजर कार्रवाई से एक बार फिर सियासत गरमा गई है। कुँवारपुर वन मंडल के तहत मनेंद्रगढ़ तिराहे पर स्थित एक मकान को वन विभाग ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

यह मकान लगभग बीस वर्षों से वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। विभाग ने कई अन्य घरों को भी चिन्हांकित किया है, जो वन भूमि पर बने हैं और उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेकर कुछ मकानों को सुरक्षित कर रहे हैं, जबकि जो रिश्वत नहीं देते, उन पर कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण, अमानवीय और निंदनीय बताते हुए कहा कि वर्षों से काबिज ग्रामीणों के घरों को इस तरह उजाड़ना सरासर गलत है। कमरो ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को निशाना बनाकर उसका मकान तोड़ा गया, जो करीब 20 वर्षों से वहीं रहकर चाय बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में किसी गरीब का आशियाना उजाड़ना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने वन विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनका दायित्व जंगलों की सुरक्षा करना है, वे पेड़ों की कटाई पर चुप रहते हैं।

कुरंदी प्लाईवुड फैक्टरी में लगी आग

जगदलपुर। जगदलपुर शहर के कुरन्दी स्थित प्लाईवुड फैक्टरी में बीती रात अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर बिग्रेड टीम को मामले की जानकारी दी गई। दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लकड़ियां जलकर खाक हो गई थी। बताया जा रहा है कि कुरन्दी स्थित फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों ने जानकारी दिया कि फैक्टरी में आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की टीम को तीन गाड़ियों के साथ रवाना किया गया। देर रात 2 घंटो तक चले इस अभियान में आग को बुझाया गया।

रायगढ़ में सरकारी जमीन पर फ्लाई ऐश डंपिंग

■ खेत भी हो रहे प्रभावित, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष ने नायब तहसीलदार से कार्रवाई की मांग की



रायगढ़। रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में समय-समय पर शिकायतें भी की जाती रही हैं, लेकिन आरोप है कि अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं, अब खरसिया ब्लॉक के नवापारा क्षेत्र की शासकीय भूमि पर उद्योगों से निकलने वाली फ्लाई ऐश को अवैध रूप से डंप किए जाने का आरोप लगाया गया है।

भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष भोलू उरांव ने इस मामले में नायब तहसीलदार को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में बताया गया है कि ग्राम नवापारा, पीएचएन-18 स्थित खसरा क्रमांक 311/1 की शासकीय भूमि पर सरडा एनर्जी कंपनी बिना शासन की विधिवत अनुमति के नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से फ्लाई ऐश डंप कर रही है।

इसके कारण पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है, जिससे आम जनजीवन और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस अवैध फ्लाई ऐश डंप में संबंधित ट्रांसपोर्टर, उद्योग प्रबंधन के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत होने की आशंका है। आरोप है कि उच्च अधिकारियों को गुमराह करने के उद्देश्य से गलत जानकारी दी जा रही है, ताकि फ्लाई ऐश का अवैध डंप लगातार जारी रह सके। आवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि सरकारी जमीन पर हो रही अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग को तत्काल रोका जाए। साथ ही आसपास की अन्य भूमि पर भी इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में शासकीय भूमि को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष भोलू उरांव ने यह भी मांग रखी है कि मामले में संलिप्त दोषी उद्योग प्रबंधन, ट्रांसपोर्टर और संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।

भोलू उरांव ने बताया कि जिस सरकारी जमीन पर फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डंप किया जा रहा है, उससे सटी कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है। बिना तिरपाल ढके फ्लाई ऐश के परिवहन के कारण आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि पहले भी यहां फ्लाई ऐश डंप किया गया था, जिसकी शिकायत के बाद उसे रुकवाया गया था। इसके बावजूद कुछ समय बाद फिर से अवैध डंपिंग शुरू हो गई है।

बालको में कर्मचारियों का आंदोलन जारी



कोरबा। शुक्रवार की सुबह से ही भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको) के प्रोजेक्ट में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने बागी रुख अपनाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। एलएंडटी कंपनी में कार्यरत मजदूर कल से हड़ताल पर हैं और आज भी उन्होंने सुबह से काम बंद रखकर प्रोजेक्ट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया।

आंदोलनरत मजदूरों ने प्लांट के भीतर स्थित प्रोजेक्ट ऑफिस और अन्य कार्यालयों का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन से पूरे प्रोजेक्ट में कामकाज ठप हो गया है। मजदूरों की प्रमुख मांग है कि उन्हें अन्य प्लांट्स की तरह केंद्र के समान वेतन और सुविधाएं दी जाएं। उनका कहना है कि पानीपत और सिंगरौली जैसे प्लांट्स में कर्मचारियों को अधिक दर पर भुगतान किया जा रहा है, जबकि बालको में अब भी पुराने रेट लागू हैं, जिससे मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है।

हड़ताल के कारण प्रोजेक्ट में चल रहे सभी निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। इस आंदोलन में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और उनके सहायक बड़ी संख्या में शामिल हैं। बताया जा रहा कि बालको प्लांट के अंदर के कई कंपनियां काम करती है और सैकड़ों मजदूर हैं, जो अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं, सुबह से आंदोलन की सूचना मिलते हैं काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वही बालको प्रबंधन और मजदूरों के बीच वार्ता के बाद ही यह आंदोलन समाप्त हो सकेगा। फिलहाल, बालको प्रबंधन की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पोगभेज्जी के उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं, व्यवस्था चरमराई, इलाज हेतु भटक रहे ग्रामीण



जगदलपुर। नक्सल प्रभावित रहे सुकमा जिला में भले ही हालात बदलने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अब भी सवालों के घेरे में है। जिले के ग्राम पंचायत पोगभेज्जी में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कहानी बयां कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3000 की आबादी के लिए बनाए गए इस उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं है। पूरे केंद्र की जिम्मेदारी महज एक स्टाफ नर्स के भरोसे चल रही है, जबकि अन्य कोई स्वास्थ्यकर्मी भी नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता। गुरुवार को दोपहर करीब 12.30 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ मिला। दिन के समय ही स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों के अनुसार, केंद्र में तैनात एकमात्र नर्स भी नियमित रूप से मौजूद नहीं रहती। वह तीन से चार दिनों में एक बार आती हैं और करीब दो घंटे रुकने के बाद वापस चली जाती हैं। जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र में रहने की व्यवस्था भी मौजूद है, फिर भी रात में कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं ठहरता। आरोप है कि सामान्य बीमारियों जैसे निमोनिया के इलाज के लिए भी जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोगभेज्जी और सिरसट्टी पंचायत के करीब 3000 ग्रामीण इस एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अमित कुमार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) से मांग की है कि यहां नियमित रूप से डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति की जाए और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

मंदिर के विवाद ने लिया हिंसक रूप, इलाके में सनसनी



बालोद। बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीभाठ में बीती रात मंदिर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के शीतला मंदिर को लेकर आयोजित एक बैठक के दौरान हुए विवाद में उप-सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीभाठ में बीती रात मंदिर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के शीतला मंदिर को लेकर आयोजित एक बैठक के दौरान हुए विवाद में उप-सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित पांच संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बटेरा के आश्रित ग्राम जोगीभाठ में बीती रात शीतला मंदिर के विषय को लेकर ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई थी। चर्चा के दौरान ग्रामीणों और उप-सरपंच डोमेन्द्र देशमुख के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि वहां मौजूद सोहन लाल साहू और उसके साथियों ने हमला कर दिया। जब उप-सरपंच का भतीजा कुणाल देशमुख बीच-बचाव करने पहुंचा, तब आरोपी सोहन लाल ने उस पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में कुणाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डौंडीलोहारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोहन लाल साहू समेत कुल 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है।

डॉक्टरों व स्टाफ को जान से मारने की धमकी, 4 गिरफ्तार



कबीरधाम। जिले के पंडरिया के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आधी रात को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टरों और स्टाफ के साथ जमकर अभद्रता और मारपीट की। घटना 1-2 अप्रैल की दरम्यानी रात की बताई जा रही है। मिली जानकारी अनुसार, आरोपियों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों व कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथापाई की और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। अचानक हुए इस हंगामे से अस्पताल परिसर में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थाना पंडरिया पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करते हुए शांति व्यवस्था बहाल की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों- दिनेश जोगी, कमल पाटले, देवकुमार टंडन और जितेंद्र बंजारे को गिरफ्तार कर लिया। पंडरिया एसडीओपी भूपत सिंह धनेश्री ने बताया कि इस कार्रवाई में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सभी को न्यायालय में पेश कर सीधे जेल भेज दिया गया।आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिससे उनकी पृष्ठभूमि संदिग्ध मानी जा रही है। कबीरधाम पुलिस ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने और चिकित्सा कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आम जनता से कानून का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

किराना दुकान में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। जिले के ग्राम बीरगहनी चौक के पास स्थित किराना दुकान से लगभग 10 हजार रुपए के सामनों की चोरी के दो आरोपी अमित पटेल (19 वर्ष), राजवीर सिंह (19 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के राशन सामानों को जब्त किया गया है। बीरगहनी चौक स्थित किराना दुकान के संचालक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 31 मार्च की रात को दुकान बंद कर घर चला गया। 1 अप्रैल की सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ था। अज्ञात चोरों में राशन सामान लगभग 10 हजार रुपए की चोरी की गई है। सिटी कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। इस दौरान आस पास के सीसीटीवी कैमरे की तलाशी लेने पर दो युवक संदेही अमित पटेल, राजवीर सिंह घूमते नजर आए। जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पुलिस को गुमराह किया गया। जब कड़ाई से पूछा गया तो किराना दुकान में चोरी की बात को दोनो ने स्वीकार की है। आरोपियों के निशान देह पर चोरी के सामनों को जब्त किया गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अन्य विभागों नही करने ज्ञापन

बीजापुर। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपने मूल कार्य के अलावा अन्य विभागों के कार्य में लगाए जाने पर आपत्ति जताई है। इस संबंध में शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 घंटे का निर्धारित कार्य समय होने के बावजूद अन्य विभागों के कार्यों में भी लगाया जा रहा है। इससे न केवल उनका मूल कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि उन्हें मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने उल्लेख किया कि शासन द्वारा पूर्व में आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आईसीडीएस विभाग के अलावा अन्य कार्य नहीं लिए जाएंगे। इसके बावजूद उन्हें बएलओ ड्यूटी, सर्वे कार्य सहित अन्य जिम्मेदारियों में लगातार लगाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि छोटे बच्चों की देखभाल और पोषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है।

भानुप्रतापपुर में आदित्य क्रिकेट अकादमी का शुभारंभ

कांकेर। जिले के भानुप्रतापपुर नगर में क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आदित्य क्रिकेट अकादमी का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अकादमी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में ड्यूस बॉल क्रिकेट को पुनर्जीवित करना है, युवा खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण देना तथा उनमें अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना का विकास करना है। अकादमी विशेष रूप से अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-18 आयु वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, ताकि कम उम्र से ही खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें सही दिशा में प्रशिक्षित किया जा सके। इस अवसर पर आयोजकों ने बताया कि अकादमी का उद्घाटन दिवंगत अखिल सिंह राठौर के विजन को समर्पित किया गया है। स्व. अखिल सिंह राठौर का सपना था कि भानुप्रतापपुर में ऐसी क्रिकेट एकेडमी स्थापित किया जाए, जहां बच्चों को वास्तविक क्रिकेट का प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक खिलाड़ियों को मैदान से जोड़े रखा।

बेलाकछार जंगल में मिले दो युवकों के शव पेड़ पर लटके

कोरबा। बालको थाना क्षेत्र के बेलाकछार जंगल में दो युवकों के शव पेड़ पर लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान प्रमोद कंवर (28 वर्ष) और अमित माथुर (27 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों बेला कछार बस्ती के निवासी थे और आपस में गहरे मित्र थे। वे भारत एल्युमिनियम लिमिटेड (बालको) में ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन पिछले एक महीने से काम पर नहीं जा रहे थे। दोनों शादीशुदा थे और इनमें से एक युवक का एक बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोनों युवक घर से घूमने जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। गुरुवार को ग्रामीणों ने जंगल में पेड़ पर लटके शव देखे और सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और जांच शुरू की। बालको पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए आत्महत्या सहित अन्य संभावित कारणों से जांच शुरू की।

जीएनए कॉलेज में लैंगिक उत्पीड़न पर व्याख्यान का आयोजन

भाटापारा। शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति एवं आंतरिक शिकायत समिति के संयुक्त तत्वावधान में कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं स्टाफ को कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता, अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता ईरम सिद्दिकी ने कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की विभिन्न स्थितियों, इसके दुष्परिणामों तथा इससे जुड़े प्रमुख कानूनों जैसे पॉश अधिनियम 2013 (कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है और पीड़ित को न्याय दिलाने हेतु स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विशिष्ट वक्ता के रूप में गोविंद सारंग विधि महाविद्यालय से डॉ. रामाशीष श्रीवास्तव ने महिला उत्पीड़न के सामाजिक एवं कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला।

अफीम की खेती मामला: कृषि विस्तार अधिकारी का निलंबन बहाल

■ अब तक 7 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी



दुर्ग। दुर्ग जिले में अफीम की खेती मामले में निलंबित कृषि विस्तार अधिकारी को बहाल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित की गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू का निलंबन बहाल कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक सात लोगों को जेल भेजा जा चुका है।

दरअसल दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में मक्के की फसल बताकर अफीम की खेती करने वाले भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया था। एकता साहू पर आरोप था कि उन्होंने खेतों में जाकर सर्वेक्षण नहीं किया, जिसके कारण कागजों में मक्के की फसल बताकर जमीन में अफीम की खेती होती रही। वहीं इस पूरे मामले में अब तक सात लोगों को जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल एकता साहू को विकासखंड धमधा के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।

5 एकड़ जमीन पर की गई थी अफीम की खेती

बता दें कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में मक्के की फसल की आड़ में करीब 5 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई थी। इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मौके से करीब 8 करोड़ रुपए कीमत की अफीम जब्त की और सभी पौधों को उखाड़कर नष्ट किया।

स्कॉटलैण्ड 103 करोड़ रुपए का डीडी क्लियर कराने के नाम पर ठगी



बिलासपुर। बिलासपुर में कैंसर अस्पताल खोलने के नाम पर वकील से करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को स्कॉटलैंड से 103 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजने का झांसा दिया। इस रकम को क्लियर कराने के नाम पर अलग-अलग प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के बहाने 3 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। काफी समय तक डिमांड ड्राफ्ट क्लियर नहीं होने पर पीड़ित को संदेह हुआ। जांच करने पर खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पीड़ित के बैंक कर्मी दोस्त पर ठगी के आरोप लगे हैं, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित वकील का नाम अरुण मिश्रा है, जबकि उसका दोस्त ।ष्ठस्नष्ट बैंक में काम करता है। आरोप है कि उसने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस उससे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह

रायगढ़। रायगढ़ में नाबालिग लड़के की शादी कराई जा रही थी। शुक्रवार को बारात निकलनी थी, लेकिन उससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गांव पहुंच गई। दस्तावेजों की जांच में दूल्हा नाबालिग पाया गया। इसके बाद संयुक्त टीम ने बाल विवाह रुकवा दिया। परिजनों ने बालिग होने तक शादी टालने का संकल्प लिया। यह करीब 8 दिनों में बाल विवाह रोकने की दूसरी कार्रवाई है। दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली थी कि रायगढ़ विकासखंड के एक गांव में नाबालिग बालक के विवाह की तैयारी चल रही है। बालक की आयु शादी के लिए निर्धारित 21 साल से कम होने के बावजूद 3 अप्रैल शुक्रवार को बारात ले जाने की तैयारी की जा रही थी। सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास विभाग के नेतृत्व में पुलिस विभाग के सहयोग से संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम गुरुवार को गांव पहुंची और बालक की जन्मतिथि से जुड़े शैक्षणिक और अन्य दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि बालक की वर्तमान आयु 20 साल 5 माह है, जो कि विवाह के लिए निर्धारित कानूनी आयु (21) से कम है। मौके पर बालक के परिजनों को बाल विवाह के कानूनी दुष्परिणामों और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाइश दी गई।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

खामोश करवाया गया हूँ हारा नहीं हूँ : राघव चड्ढा



नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर मचे आंतरिक घमासान के बीच एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला है। राज्यसभा में पार्टी के चर्चित चेहरे राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर (उप-नेता) के पद से हटा दिया गया है। इस फैसले के बाद चड्ढा ने एक कड़ा और भावुक बयान जारी करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें खामोश तो किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। राघव चड्ढा के लिए अब यह साफ़ हो गया है कि पार्टी के भीतर अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन में डिप्टी लीडर पद से हटाने और उनकी जगह सांसद अशोक कुमार मित्तल को इस पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा, अशोक कुमार मित्तल राज्यसभा में आप के नए डिप्टी लीडर होंगे।

पीएम मोदी से सवाल करने से डरते क्यों हो राघव : भारद्वाज



नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा को सलाह दी कि वे संसद के समय का उपयोग समोसे जैसे हल्के-फुल्के जनसंपर्क के लिए करने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से बड़ी समस्याओं पर निडर होकर सवाल करें। चड्ढा के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भारद्वाज ने पंजाब के राज्यसभा सांसद से पूछा कि वे राज्य के मुद्दों को उठाने से क्यों डर रहे हैं और राज्यसभा में समोसे की बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी विपक्ष किसी मुद्दे पर संसद से वॉकआउट करता है, आप उसमें शामिल नहीं होते। काफी समय से मैंने आपको संसद में ऐसा कोई मुद्दा उठाते नहीं देखा, जिसमें आपने सीधे प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हों। इस तरह के डर के माहौल में राजनीति कैसे चल सकती है? उन्होंने पूछा कि आप पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपको पंजाब के मुद्दे उठाने चाहिए। आप उन्हें उठाने से क्यों डरते हैं?

आप में केजरीवाल से मतभेद पर भाजपा का बड़ा हमला



नईदिल्ली। राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने के बाद विपक्ष ने आम आदमी पार्टी (आप) पर अपना हमला तेज कर दिया है, और कई नेताओं ने इस कदम को पार्टी के भीतर गहरी दरार का संकेत बताया है। भाजपा के रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि राघव चड्ढा दिल्ली विधानसभा में मेरे साथ रहे हैं, वे एक अच्छे वक्ता हैं। अगर आप नेतृत्व ने उनके बोलने पर रोक लगा दी है, तो यह सरासर तानाशाही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि राघव चड्ढा को जिस तरह से दरकिनार किया गया है और किनारे कर दिया गया है, उससे साफ पता चलता है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के अराजक और भ्रष्ट नेतृत्व से खुद को अलग कर लिया है। सचदेवा ने आगे दावा किया कि स्वाति मालीवाल के बाद चड्ढा दूसरे प्रमुख आम आदमी नेता हैं जिनके नेतृत्व से मतभेद हैं, जो केजरीवाल की कार्यशैली से अलग होते दिख रहे हैं।

बंगाल बंधक विवाद मामले में एआईएमआईएम नेता गिरफ्तार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता और पेशे से वकील मोफ़क्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का आरोप है कि इस्लाम ही उस हिंसक विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड था, जिसने राज्य की कानून-व्यवस्था और न्यायपालिका की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेशे से वकील और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इटाहार से एआईएमआईएम के उम्मीदवार रहे इस्लाम को मालदा घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उन्हें बागडोगरा हवाई अड्डे पर तब गिरफ़्तार किया गया, जब वे राज्य से भागने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव वाले पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख कर रहे सात न्यायिक अधिकारियों को बुधवार को नौ घंटे से ज़्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया था।

पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरे ओवैसी के 12 सिपाही



कोलकाता। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने शुक्रवार (3 अप्रैल) को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने रघुनाथगंज से इमरान सोआंकी, आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज, कंडी से मिस्बाहुल इस्लाम खान, सुजापुर से रेजाउल करीम और मोथाबारी से एडवोकेट मोहम्मद मुस्तहिद हक को मैदान में उतारा है। नलहाटी से हाजी अंसार एसके साहब और मोरारी से तासीर एसके साहब चुनाव लड़ेंगे। बारासात से एआईएमआईएम ने मोनाएम सरदार को और करांडीघी से महबूब आलम को उम्मीदवार बनाया है। सूती से असदुल एसके, बसीरहाट दक्षिण से शबाना परवीन और हबरा से आसिक राज ममोंडल को मनोनीत किया गया है। एआईएमआईएम, हुमायूं कबीर द्वारा गठित एजेयूपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है।

संसद के विशेष सत्र से पहले सियासी घमासान

महिला आरक्षण बिल पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने



नईदिल्ली। संसद का बजट सत्र 16 अप्रैल को थोड़े समय के विराम के बाद पुनः शुरू होगा और सभी की निगाहें महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर टिकी हैं। सरकार लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना बना रही है ताकि महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, सत्र लगभग तीन दिनों तक चल सकता है और प्रस्तावित विधेयकों को सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।

यह योजना नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना है। सरकार का मानना है कि कानून को लागू करने का समय आ गया है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वह विपक्षी दलों के संपर्क में है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को निर्धारित है। 16 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी के साथ चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की। वे महिला आरक्षण विधेयक, 2023 में कुछ संशोधन करना चाहते थे। किरेन रिजिजू का यह पत्र 16 मार्च को प्राप्त हुआ।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि खरगे जी ने उसी दिन किरेन रिजिजू को जवाब देते हुए कहा, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन कृपया सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सभी विपक्षी दलों को एक साथ बुलाएं, और हम इस पर चर्चा करेंगे। कृपया अपना प्रस्ताव लिखित में प्रस्तुत करें। 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दलों ने इस पत्र से सहमति जताई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी नेताओं ने किरेन रिजिजू को जवाब में लिखा, आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं... कृपया सर्वदलीय बैठक बुलाएं। 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए।

इस मुद्दे ने राज्यसभा में तीखी बहस छेड़ दी है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कानून कब लाया जाए, यह तय करने का अधिकार सरकार के पास है। वहीं, कई विपक्षी सदस्यों ने चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक की मांग की। संजय सिंह जैसे नेताओं ने भी सरकार पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कुछ सांसदों ने व्यापक चिंताएं जताईं। फौजिया खान ने सवाल उठाया कि क्या राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में भी इसी तरह का आरक्षण लागू होगा। मनोज झा ने पूछा कि क्या आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए उप-कोटा होगा।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार को घेरा

स्ट्रैट ऑफ होर्मुज पर सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल





नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रयासों में पारदर्शिता बरतने का आह्वान किया। उन्होंने इस मार्ग से होने वाले कच्चे तेल के परिवहन में आई भारी कमी को उजागर किया, जो पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले प्रतिदिन 22 मिलियन बैरल था, लेकिन अब घटकर मात्र 0.5 मिलियन बैरल रह गया है। तिवारी ने कहा कि मूल बात यह है कि तुर्की, मिस्र और चीन इस दिशा में पहल कर रहे हैं; इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में कुछ बैठकें हुई हैं। लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य तक पहुंच के संभावित नुकसान के संबंध में सरकार कूटनीतिक दृष्टिकोण से क्या पहल कर रही है? 28 फरवरी से पहले इस मार्ग से प्रतिदिन 22 मिलियन बैरल कच्चे तेल का परिवहन होता था, जो अब घटकर 0.5 मिलियन बैरल रह गया है।

उन्होंने भारतीय सरकार से जलडमरूमध्य से तेल प्रवाह बहाल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को स्पष्ट करने का आग्रह किया और कहा कि इस तेल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी चीन को भेजा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने कुछ रियायतें हासिल कर ली हैं। वहीं, भारत को केवल दो या तीन टैंकर ही मिले हैं। फिर भी, इस स्पष्ट अंतर पर गौर करें- प्रतिदिन 22 मिलियन बैरल से घटकर मात्र 0.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य की निरंतर सुगमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार (स्थानीय समय) को बहरीन द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने वाली है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव में सदस्य देशों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित पारगमन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक रक्षात्मक साधनों का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य की प्रभावी नाकाबंदी के कारण ऊर्जा व्यापार में उत्पन्न महत्वपूर्ण बाधाओं के बीच आया है।

कांग्रेस पार्टी से अलग सुर, आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया संकट पर एनडीए सरकार की नीति को सराहा

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने गुरुवार को पश्चिम एशिया में संकट से निपटने के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कूटनीतिक दृष्टिकोण को परिपक्व और कुशल बताया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए एक परिपक्व प्रतिक्रिया को समय की आवश्यकता बताया। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संकट से निपटने में भारत की कूटनीति परिपक्व और कुशल रही है, जिससे संभावित जोखिमों से बचा जा सका है। भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ संकल्प पर आधारित होनी चाहिए। सरकार ने राजनीतिक दलों के नेतृत्व को स्थिति और इस अनिश्चित और अस्थिर परिस्थिति में लिए गए नीतिगत निर्णयों से अवगत कराने के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित की है।

आनंद शर्मा ने आगे कहा कि यह राष्ट्रीय संवाद जारी रहना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित परिपक्व प्रतिक्रिया समय की आवश्यकता है। शर्मा ने भविष्यवाणी की कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से रुपये का अवमूल्यन हो सकता है, और इस चुनौती से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जब नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था पतन के कगार पर है, तब संवाद जारी रखा जाए।

उन्होंने कहा कि युद्ध ने ऊर्जा, आर्थिक और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, विश्व बाजारों में अस्थिरता और रुपये तथा राष्ट्रीय मुद्राओं के तीव्र अवमूल्यन से तात्कालिक और दीर्घकालिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे तत्काल निपटना आवश्यक है। संकट की गंभीरता को पूरी तरह से समझना होगा। नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था और वैश्विक संकट प्रबंधन तंत्र के पतन पर विश्व मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। शर्मा के विचार कांग्रेस से भिन्न हैं, जिसने देश में एलपीजी आपूर्ति की खराब स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए लगातार उसकी आलोचना की है। इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भारत को अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में दरकिनार कर दिया गया है और प्रधानमंत्री को समझौतावादी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की निजी विदेश नीति है। इसका परिणाम आप देख सकते हैं। यह एक सर्वव्यापी मजाक है। हर कोई इसे एक सर्वव्यापी मजाक मानता है।

खेल
प्रमुख समाचार

दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला आज



नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान मिचेल सैंटनर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले आईपीएल मैच से पहले मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ गए। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम शनिवार दोपहर को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगी। सैंटनर और इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ही मुंबई इंडियंस से जुड़ने वाले आखिरी दो खिलाड़ी बचे थे। मुंबई इंडियंस ने पिछले रविवार को मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ अपना पहला मैच शानदार तरीके से जीता था।

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में केकेआर को छह विकेट से हराया था। केकेआर से मिले 221 रनों के लक्ष्य को मुंबई ने 19.1 ओवर में सिर्फ चार विकेट खोकर हासिल कर लिया था। यह आईपीएल में मुंबई का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज भी रहा। मुंबई की ओर से रेयान रिकेल्टन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 81 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि रोहित शर्मा ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन बनाए थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए मिलकर 11.5 ओवर में 148 रन जोड़े थे और मैच को पूरी तरह से एकतरफा कर दिया था। हालांकि, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का प्रदर्शन केकेआर के खिलाफ निराशाजनक रहा था। मुंबई को पहले ही मैच में मिचेल सैंटनर के अनुभव की कमी बीच के ओवरों में साफतौर पर खली थी। अल्लाह गजनफर को स्पिनर के तौर पर प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई थी। हालांकि, गजनफर काफी महंगे साबित हुए थे और उन्होंने चार ओवर में बिना कोई विकेट चटकाए 51 रन खर्च किए थे। वहीं, मयंक मारकंडे से कप्तान हार्दिक ने सिर्फ एक ही ओवर करवाया था, जिसमें उन्होंने 16 रन दे दिए थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

बढ़ सकते हैं चीनी के दाम! समय से पहले मिलें बंद

नईदिल्ली। भारत में चीनी उत्पादन लगातार दूसरे साल घरेलू खपत से कम रहने की आशंका है। गन्ने की कमजोर पैदावार के चलते चीनी मिलें इस बार सामान्य से पहले बंद हो रही हैं, जिससे बाजार में सप्लाई दबाव में आ सकती है और कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। उद्योग से जुड़े जानकारों के मुताबिक, इस सीजन में कुल उत्पादन करीब 2.8 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास रहने का अनुमान है, जो शुरुआती आकलन से काफी कम है। सीजन की शुरुआत में ISMA और NFCSF ने करीब 3.1 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान लगाया था, जबकि घरेलू मांग 2.9 करोड़ टन के आसपास बताई गई थी। इस साल गन्ने की पैदावार पर अत्यधिक बारिश का असर पड़ा है। NFCSF के आंकड़ों के अनुसार, इस साल शुरू हुई 541 मिलों में से 467 मिलें मार्च के अंत तक बंद हो चुकी हैं, पिछले साल इसी समय तक 420 मिलें बंद हुई थीं।

महंगाई का एक और झटका सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी

नईदिल्ली। देश में महंगाई के बीच एक और झटका लगा है। अडाणी टोटल गैस ने सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) की कीमतों में 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के लागू होने के बाद सीएनजी की कीमत 82.27 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 83.77 रुपए प्रति किलो हो गई है। यह बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना सफर के लिए सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। खासकर टैक्सी, ऑटो और अन्य कमर्शियल वाहन चालकों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर किराए पर भी पड़ सकता है। एनर्जी सेक्टर्स के जानकारों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव और इनपुट लागत बढ़ने के चलते कंपनियां दाम बढ़ाने को मजबूर हैं।

चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन में 6 लाख की भारी गिरावट

देहरादून। उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा इस साल मुश्किल दौर से गुजर रही है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली इस पावन यात्रा पर वैश्विक तनाव और युद्ध के बादलों ने ग्रहण लगा दिया है। यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 6 लाख कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो सीधे तौर पर राज्य के पर्यटन उद्योग के लिए खतरे की घंटी है। आंकड़े गवाह हैं कि इस बार यात्रियों के मन में डर और अनिश्चितता का माहौल है। पिछले साल शुरुआती 26 दिनों में ही 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया था। इस साल यह संख्या सिमटकर मात्र 11,07,841 रह गई है। यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 6 लाख कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो सीधे तौर पर राज्य के पर्यटन उद्योग के लिए खतरे की घंटी है। पिछले साल के मुताबिक श्रद्धालुओं के उत्साह में भारी कमी देखी जा रही है जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबारी बेहद चिंतित हैं।

अब बिना ओटीपी के होगा वेरिफिकेशन

नईदिल्ली। देश के बड़े प्राइवेट बैंक और टेलिकॉम कंपनियां अब डिजिटल सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में हैं। पारंपरिक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) सिस्टम को धीरे-धीरे हटाकर उसकी जगह 'साइलेंट ऑथेंटिकेशन' मैकेनिज्म लाने पर काम हो रहा है। इस नई तकनीक के तहत बैंक बैकग्राउंड में ही यह जांच करेंगे कि बैंक ऐप से जुड़ा मोबाइल नंबर उसी फोन में मौजूद सिम से मैच कर रहा है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो ट्रांजैक्शन को तुरंत संदिग्ध मानकर ब्लॉक किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में ग्राहक को कोई अतिरिक्त स्टेप नहीं करना होगा और यह ई-सिम पर भी प्रभावी तरीके से काम करेगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सिम क्लोनिंग और ई-सिम स्वैप जैसे फ्रॉड को रोकना है।

टैरिफ मुक्त डिजिटल व्यापार से ग्लोबल साउथ को नुकसान

प्रो अश्विनी महाजन

वर्ष 1998 में, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की घोषणा को अपनाया था और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी न लगाने की प्रथा को जारी रखने पर सहमति जतायी थी। हालांकि यह रोक अगली मंत्रिस्तरीय बैठक शुरू होने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान थी। पर डब्ल्यूटीओ की हर मंत्रिस्तरीय बैठक में इस रोक को अगली बैठक तक के लिए बढ़ाया जाता रहा है। इस बार भी इस पर सहमति नहीं बन पायी। डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जिसका आयोजन कैमरून में (26-29 मार्च तक) हुआ, इ-ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी पर रोक को लेकर बिना सर्वसम्मति के ही समाप्त हो गया। डब्ल्यूटीओ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर लगी रोक एक ऐसा प्रावधान है, जो देशों को इंटरनेट के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने वाले डिजिटल उत्पादों पर टैरिफ लगाने से रोकता है। जब डब्ल्यूटीओ शुरू हुआ था, तब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का व्यापार सीमित था। सो, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापार पर लगने वाले टैरिफ को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।

वर्ष 1998 में डब्ल्यूटीओ के दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में यह तय किया गया कि विकासशील देशों की विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से जुड़े मुद्दों का अध्ययन किया जाये। यह प्रस्ताव भी रखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक के लिए टाल दिया जाये। पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देश, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर लगने वाले सीमा शुल्क पर डब्ल्यूटीओ की



इस रोक को स्थायी (या अनिश्चित काल के लिए) बनाये रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल उत्पादों के आयात के लिए सबसे ज्यादा माना जाने वाला पैमाना है डिजिटल रूप से दी जाने वाली सेवाएं, जैसे सॉफ्टवेयर, क्लाउड, ओटीटी, डाटा, डिजाइन, फिनटेक आदि। नीति आयोग के अनुमानों के मुताबिक, भारत ने 2024 में 116.9 अरब डॉलर की डिजिटल सेवाएं आयात कीं, जो पिछले वर्षों के 41.4 अरब डॉलर से बहुत अधिक है।

इ-ट्रांसमिशन पर डब्ल्यूटीओ की रोक का राजस्व पर बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड, इ-बुक्स, फिल्में, क्लाउड सेवाएं आदि, पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। वर्ष 2017 में राजस्व के इस नुकसान का अनुमान 50 करोड़ डॉलर लगाया गया था, लेकिन अब स्ट्रीमिंग, डिजिटल फिल्में, किताबें, एआइ टूल्स, गेमिंग आदि के आयात में जबरदस्त वृद्धि के कारण यह नुकसान कहीं अधिक होने की संभावना है। उधर अमेरिका यूरोपीय संघ और जापान के साथ मिलकर टैरिफ मुक्त डिजिटल व्यापार को बनाये रखने के लिए इस रोक को स्थायी रूप से अपनाने की पैरवी भी कर रहा है। अमेरिका की ओर से पहला तर्क यह है कि डिजिटल टैरिफ वैश्विक डिजिटल व्यापार में बाधा डालेंगे। दूसरा, इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है। तीसरा, यह वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को खंडित कर देगा।

इ-ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी पर रोक समाप्त होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इससे राजस्व का भारी नुकसान होता है, क्योंकि भारत सहित विकासशील देश इ-प्रोडक्ट्स (डिजिटल प्रोडक्ट्स) के नेट इंपोर्टर है। दूसरा, हमारे स्टार्ट-अप और सॉफ्टवेयर कंपनियां कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में सक्षम हैं। हम अपने ही देश में फिल्में और दूसरे मनोरंजन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पर जब ऐसे सभी प्रोडक्ट्स बिना किसी रोक-टोक के, बिना टैरिफ के आयात किये जाते हैं, तो उन्हें देश में बनाने का प्रोत्साहन कम हो जाता है। इ-प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने पर लगी रोक असल में 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रयासों को खत्म कर रही है।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 : मल्लखंभ प्रतियोगिता का शानदार समापन

मल्लखंभ में लहराया परचम, बालक-बालिका दोनों वर्गों में बने चौंपियन





रायपुर। खेलो इंडिया ट्राईबल गेम्स 2026 के अंतर्गत सरगुजा जिले के अम्बिकापुर के गांधी स्टेडियम में आयोजित डेमो खेल मल्लखंभ प्रतियोगिता का शानदार समापन शुक्रवार को हुआ।

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने रोप मल्लखंभ, पोल मल्लखंभ, हैंगिंग मल्लखंभ, पिरामिड मल्लखंभ में एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर वहां मौजूद दर्शकों द्वारा तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता के बाद विजेता टीम घोषित किया गया। आज हुई प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ विजेता घोषित की गई। विजेता टीमों को शनिवार को आयोजित मेडल सेरेमनी में मेडल प्रदान किया जाएगा।

ये रहे चौंपियन

मल्लखंभ प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। राज्यों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर जीत के लिए दमखम लगाया। छत्तीसगढ़ की टीम ने बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 124.35 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 118.35 अंक के साथ सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 86.95 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

वहीं बलिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 80.15 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 69.90 अंक के सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 49.80 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

जल संरक्षण के कार्यों को और गति दे: राज्यपाल डेका



रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जल संरक्षण के कार्यों की सराहना करते हुए किसानों को डबरी खनन के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि विकासखंड में 218 डबरी स्वीकृत की गई हैं तथा बड़ी संख्या में निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं, राज्यपाल ने और गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल श्री डेका ने आज सरायपाली प्रवास के दौरान रेस्ट हाउस में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

राज्यपाल ने वृक्षारोपण को जनआंदोलन के रूप में संचालित करने पर जोर देते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जाए। कैंपा एवं मनरेगा मद से वृहत वृक्षारोपण करते हुए शासकीय भवनों, रेस्ट हाउस परिसरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार एवं छायादार पौधे लगाए जाएं। विभाग ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख पौधरोपण किया गया है तथा अमृत सरोवरों के आसपास भी हरित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यपाल ने कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने तथा धान के साथ उद्यानिकी फसलों के समावेश पर बल दिया। उन्होंने जैविक चावल के वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रभावी बनाने, हितग्राहियों से सेवा शुल्क लेने तथा सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने टीबी रोगियों की जानकारी ली और उनके उपचार की सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने समाज के सक्षम व्यक्तियों को टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने, रेडक्रॉस से जुड़ने तथा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एवं मोतियाबिंद के उपचार हेतु जागरूकता अभियान एवं शिविर आयोजित करने पर बल दिया।

भाजपा की कार्य पद्धति: संगठन, अनुशासन और सेवा का सशक्त आधार: राजेन्द्र शर्मा



रायपुर। रायपुर शहर जिला भाजपा प्रभारी ने पुरानी बस्ती मण्डल के प्रशिक्षण वर्ग में कार्य पद्धति विषय में संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्य पद्धति एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठन को प्रभावी, अनुशासित एवं परिणामकारी ढंग से संचालित करने की दिशा प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि कार्य पद्धति का अर्थ कार्य करने की विधि, प्रणाली एवं शैली है। की कार्य पद्धति संगठनात्मक अनुशासन, सुदृढ़ विचारधारा एवं जनसेवा के सिद्धांतों पर आधारित है।

राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि भाजपा की कार्यशैली का मूल आधार द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद है, जिसमें राष्ट्र प्रथम, अंत्योदय तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से भी सक्रिय और सजग रहता है। उन्होंने संगठन सर्वोपरि की भावना पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा में व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं तथा संगठन हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कार्यकर्ताओं में टीम भावना का विकास होता है। भाजपा की कार्य पद्धति में नियमित बैठक एवं सुनियोजित योजना का विशेष महत्व है। बूथ, मंडल, जिला एवं प्रदेश स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित कर योजना, क्रियान्वयन और समीक्षा की प्रक्रिया के तहत कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाता है।उन्होंने बूथ स्तर की मजबूती को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि मेरा बूथ ङ्क सबसे मजबूत के लक्ष्य के साथ प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहा है सेवा एवं संपर्क को भाजपा की कार्य पद्धति का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि रक्तदान, आपदा राहत एवं जन समस्याओं के समाधान जैसे कार्यों के माध्यम से कार्यकर्ता निरंतर समाज के बीच सक्रिय रहते हैं।

रेडक्रॉस प्रतिनिधियों ने राज्यपाल रमेन डेका से की सौहार्दपूर्ण भेंट



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका के आज सरायपाली प्रवास के दौरान रेडक्रास एवं एन सी सी के पदाधिकारियों ने भेंट की। कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष विनय कुमार लंगेह एवं अनुपमा आनंद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली के दिशा-निर्देशन एवं सभापति संदीप दीवान (इंडिया रेडक्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा महासमुंद) के मार्गदर्शन तथा जिला संगठक डा अशोक गिरि गोस्वामी के नेतृत्व में भारतीय रेडक्रास सोसायटी ज़िला शाखा महासमुन्द अन्तर्गत पदाधिकारियों ने मुलाकात की।सभी ने रेडक्रास गीत गाकर राज्यपाल का स्वागत किया। रेडक्रॉस काउंसलर्स एवं वालेंटियर्स की टीम ने राज्यपाल एवं पदेन अध्यक्ष इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी (राज्य शाखा, रायपुर) का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रेस्ट हाउस परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पीपल का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

विधायक मूणत ने महादेवघाट में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण



रायपुर। पश्चिम विधायक एवं प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 अंतर्गत माधव राव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के क्षेत्र महादेवघाट में विधायक निधि से 5 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण नगर निगम एमआईसी सदस्य सुमन अशोक पाण्डेय, वार्ड 69 के पार्षद महेन्द्र औसर, नगर निगम जोन 8 कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा सहित जोन 8 के अन्य सम्बंधित अधिकारियों, गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, आमजनों सहित करते हुए नगरवासियों को शानदार सौगात दी.

रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने मंच से खेलो इंडिया अभियान हेतु खिलाडियों को प्रोत्साहित करने खेल सुविधायें देने 20 लाख रूपये का स्वेच्छानुदान विधायक निधि से देने की घोषणा की. रायपुर पश्चिम विधायक और प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने महादेवघाट में 5वीं अखिल भारतीय वालीबाल स्पर्धा का नगर निगम एमआईसी सदस्य सुमन अशोक पाण्डेय, वार्ड 69 के पार्षद महेन्द्र औसर, जोन 8 कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा सहित आयोजक हटकेश्वर वालीबाल संघ और मास्टर एसोसिएशन के सैयद अनवर अली और मैक्सीन सहित अन्य पदाधिकारियों, खिलाडियों, खेलप्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति में किया. रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने मैदान में जाकर दोनों टीमों के खिलाडियों का परिचय प्राप्त किया और उन्हें अच्छा खेल प्रदर्शन करने प्रोत्साहित करते हुए आयोजन समिति पदाधिकारियों को 5वीं अखिल भारतीय वालीबाल स्पर्धा के सफल होने हेतु हार्दिक मंगलकामनायें दीं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सरकार बस्तर विकास के लिए विशेष पैकेज दे: दीपक बैज

रायपुर। कांग्रेस ने मांग किया है कि सरकार बस्तर के सभी गांव के विकास के लिए 1 करोड़ प्रति गांव की राशि तत्काल प्रदान करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने खुद घोषित किया था, बस्तर का जो गांव नक्सल मुक्त हो जाएगा उसको 1 करोड़ रू. प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री से लेकर पूरी सरकार यह बयान दे रही है कि बस्तर सहित पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है, तब



सरकार अपनी घोषणा के अनुसार बस्तर संभाग के सभी गांवों के लिए तुरंत 1 करोड़ रू. की राशि जारी किया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार तत्काल विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा करे, ताकि बस्तर को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। बस्तर की खूबसूरती की रक्षा के साथ यहां के युवाओं के लिए रोजगार और वनोपज आधारित उद्योगों के लिए सरकार विशेष कार्य योजना बनायें। बस्तर के युवाओं के लिए नौकरी के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाये सरकार। एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में खोला जाना चाहिए। एनएमडीसी भारत की वह नवरत्न कंपनी है जो लौह अयस्क तो बस्तर से निकलती है और उसे दुनिया भर में भेजती है।

सरकार उर्वरकों की उपलब्धता पर श्वेत पत्र जारी करे: शुक्ला

रायपुर। उर्वरकों की उपलब्धता पर कृषि मंत्री कोरी बयानबाजी मात्र न करे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले वर्ष भी भाजपा सरकार और कृषि मंत्री की लापरवाही के कारण पूरे खरीफ के सीजन में किसान खाद्य के संकट से जुझेहै। इस वर्ष भी ठोस प्रयास करने और उर्वरकों के समुचित इंतजाम करने के बजाए कृषि मंत्री रामविचार नेताम अभी से विपक्ष को कोसना शुरू कर चुके है। किसान



खरीफ सीजन शुरू होने के तीन महिना पहले फरवरी में ही अपनी डिमांड सोसायटी के माध्यम से सरकार तक पहुंचा देते है। सरकार का दायित्व है कि वह किसानों के मांग के अनुरूप सोसायटियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक पहुंचाएं ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके। सरकार उर्वरकों की उपलब्धता पर श्वेत पत्र जारी करे। पिछले खरीफ सीजन में राज्य के किसानों को 4.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता थी, साय सरकार शुरू के दो माह तक मात्र 80 हजार मीट्रिक टन ही उर्वरक दे पायी थी, किसान यूरिया से लेकर डीएपी और पोटाश सभी के लिए भटकते रहे, बिचौलियों के द्वारा ब्लेक मार्केट में तीन से चार गुने दाम में किसानों को यूरिया और डीएपी खरीदने को मजबूर होना पड़ा था।

डीजल में 17 प्रतिशत एवं जनता से 23 % वेट टैक्स: ठाकुर

रायपुर। भाजपा सरकार पर उद्योगपतियों से डीजल में 17 प्रतिशत एवं आम जनता से 23 प्रतिशत वेट टैक्स वसूलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने उद्योगों से 17 प्रतिशत एवं आम जनता से 23 प्रतिशत वेट एवं 1 रू. अतिरिक्त डीजल में वसूल रही है। भाजपा के कुशासन के कारण हर वर्ग पीड़ित है। सभी वर्गो को राहत देने वेट में और कटौती करना चाहिए।



आखिर डबल इंजन की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को राहत देने के लिए क्यों काम कर रही है? केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों के फायदा के लिए पेट्रोल में 3 प्रतिशत एवं डीजल 10 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी में कटौती किया लेकिन उसका लाभ उद्योगों एवं आम जनता को नहीं मिल रहा है। एक्साइज ड्यूटी कटौती के बाद आम जनता को पेट्रोल खरीदने में राहत की जो उम्मीद थी वो तो मिला नहीं, बल्कि राज्य में पेट्रोल 1 रू. 15 पैसे और महंगा हो गया। सरकार आखिर सभी वर्गो के हित में फैसला क्यों नहीं करती है? जिससे महंगाई से पीड़ित उद्योग, किसान, ट्रांसपोर्टर, बस ऑपरेटर और होटल, रेस्टोरेंट में डीजल भट्टी चलाने वाले को राहत मिल सके। भाजपा की सरकार के गलत नीतियों के चलते हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है।

शराब से राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य भाजपा का असली चरित्र : वंदना

रायपुर। आबकारी मंत्री द्वारा इस वर्ष शराब से राजस्व बढ़ाने के लक्ष्य पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पांच साल तक शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा के लिये अब शराब राजस्व बढ़ाने का साधन बन चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष सरकार ने शराब से 10700 करोड़ रू. कमाया है। आबकारी मंत्री इस वित्तीय वर्ष 13000 करोड़ राजस्व कमाने का लक्ष्य लेकर चल रहे मतलब साफ है सरकार इस साल और



शराब की बिक्री बढ़ाने पर जोर देगी। चुनाव में शराब बंदी की बात पर झूठ बोलकर कांग्रेस को कोसने वाली जनता को गुमराह कर वोट लेने वाली भाजपा को जनता सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिये। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा विपक्ष में थी तब शराब बंदी के लिए बड़ी-बड़ी बात करती थी। शराब बंदी के लिये सरकार ने पिछले 2 साल में एक कदम भी नहीं उठाया। अब शराब की बिक्री बढ़ाने में लगी है। सरकार में आने के बाद शराब की खपत बढ़ाने नीति बना रही 67 नई दुकानें खोल दिए, 700 दुकानें जो पहले से चल रही थी उनको कंपोजिट कर दिया देशी में अंग्रेजी, अंग्रेजी में देशी बेचना शुरू कर दिया, मतलब 1400 काउंटर हो गया।

महंगाई बेलगाम, रोजगार खत्म हो गया : वर्मा

रायपुर। बेलगाम हो चुकी महंगाई को भाजपा सरकार निर्मित त्रासदी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक तरफ बेरोजगारी दूसरी ओर बेतहाशा बढ़ती महंगाई की मार से जनता दोनों ओर से पिस रही है। आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इस सरकार ने देश के 81 करोड़ जनता को यह सरकार गरीब बनकर केवल 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया है।



भुखमरी इंडेक्स में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, असमानता और गरीबी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि आम आदमी की घरेलू बचत ऐतिहासिक तौर पर न्यूनतम स्तर पर आ गई है। खाद्य तेल को 70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने में 70 साल लग गए थे, लेकिन मोदी राज के चंद दिनों में ही 170 पार हो गया। घरेलू गैस सिलेंडर जो भाजपाइयों को 400 रुपए में महंगा लगाता था, उसे 980 तक पहुंचा दिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर्शियल गैस के दाम में 195 रू. की बढ़ोतरी कर दिया। इसके पहले तीन महीने में कमर्शियल गैस के दाम में 525 रू. की बढ़ोतरी हुई थी।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026

मछुआरे का काम करने वाले अब्दुल ने लिखा नया अध्याय

रायपुर। अब्दुल फताह ज़्यादातर रातों को समुद्र में होते हैं, जहां वे मछुआरे बनकर अपने परिवार की रोज़ी-रोटी कमाने में मदद करते हैं। जैसे ही सुबह होती है, वे सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर निकल पड़ते हैं और एक एक अलग सपने का पीछा करते हुए लक्षद्वीप को %खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स% 2026 में पहला मेडल दिलाया। कवरत्ती और कदमत द्वीपों के बीच स्थित, दूरदराज के अमीनी द्वीप जो लगभग 2.7 किमी लंबा और 1.2 किमी चौड़ा है, और जिसका कुल भू-क्षेत्रफल 2.60 वर्ग किमी है के 18 वर्षीय लॉन्ग जम्पर ने जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर मैदान में 7.03 मीटर की अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। यह इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था।

केंद्र शासित प्रदेश के खेल अधिकारी अहमद जावेद हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह लक्षद्वीप के पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 7 मीटर की दूरी पार की है और यह वाकई एक खास बात है। मछुआरे परिवार में जन्मे फताह भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं और घर की बड़ी ज़िम्मेदारी संभालते हैं। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद, आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। इसके बजाय, उन्होंने अपने पिता के पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बँटाने और खेल को अपने जुनून के तौर



पर अपनाने का फ़ैसला किया।

फताह ने कहा, कोई और चारा नहीं है, आपको चीज़ों में संतुलन बनाना ही पड़ता है। जब मैं स्कूल में था, तभी से मैं अपने पिता की मछली पकड़ने के काम में मदद करता आ रहा हूँ। यही हमारी आमदनी का एकमात्र ज़रिया है। हमारे परिवार में छह लोग हैं। सुबह मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ; मेरे परिवार को इस बारे में पता है, भले ही वे इस खेल के बारे में बहुत कम समझते हों।%% दिलचस्प बात यह है कि एथलेटिक्स उनका पहला प्यार नहीं था। फताह शुरू में फुटबॉल खेलते थे, जैसा कि द्वीप के कई दूसरे युवा करते थे। हालांकि, कुछ साल पहले एक स्थानीय इंटर-आइलैंड प्रतियोगिता के दौरान उनकी यात्रा में एक अहम मोड़ आया। कोच मोहम्मद कासिम ने इस युवा की दौड़ने की ज़बरदस्त काबिलियत को पहचाना और उन्हें एथलेटिक्स में आने का सुझाव दिया।

तब से, फताह ने लॉन्ग जंप और 100-मीटर स्प्रिंट में ट्रेनिंग शुरू कर दी। लगभग उसी समय, अमिनी एथलेटिक्स एसोसिएशन का गठन होने लगा, जिससे इस क्षेत्र में खेलों के विकास को एक सही ढाँचा मिला। फताह और कई अन्य युवा एथलीटों को धीरे-धीरे कोचिंग की मदद दी गई, जिससे उन्हें ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग करने में मदद मिली। सिर्फ़ दो सालों में, एसोसिएशन ने लगभग 384 एथलीटों को तैयार किया। इस समूह में से, 17 एथलीटों को गेम्स में लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया।

प्राचीन दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा



रायपुर। फाफाडीह रमण मंदिर वार्ड स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव श्री दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर द्वारा आयोजित 18 वां वर्ष हनुमान जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया।मंदिर समिति संयोजक घनश्याम राजू तिवारी ने बताया की श्री हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें विशेष रूप दुर्ग से बुलवायी गयी भगवान श्रीराम भक्त हनुमान जी की मूर्ती रथ पर सवार झांकी ने अनेक लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया, भक्तिमय डी.जे. धुन पर नाचते झूमते हुए जय जय सियाराम के नारे लगाते महिला, पुरुष, युवा ने खूब आंनद उठाया और आस्था प्रकट की।

मंदिर प्रांगण में पूजन हवन के पश्चात भंडारा रखा गया था, जिसमे हजारो लोगो ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। संध्या 06 बजे संगीतमय धुन में सुंदरकांड पाठ हनुमान चालीसा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अंशु महराज की भजन मंडली द्वारा देर रात्रि तक संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान भजन की प्रस्तुती ने भक्तों का मन मोहित कर दिया।

मंदिर समिति संयोजक घनश्याम राजू तिवारी ने श्री हनुमान जन्मोत्सव 2026 के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम को सफल बनाने समिति सदस्यों, आयोजन में पधारे समस्त माताओ, भाई, बहनों, युवा भक्तो एवं प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.